छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र



हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन



जिले का प्रथम दैनिक समाचार पत्र स्थापना वर्ष 2020

E-mail: eksatbulletin@gmail.com | गौरेला पेंड्रा मरवाही, शुक्रवार 13 नवंबर 2026 | वर्ष-07, अंक-134 पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए | Website: www.eksatbulletin.in

युवा उत्सव में बिखरी लोक संस्कृति की अनुपम छटा, युवाओं ने दिखाई कला और प्रतिभा की झलक

कलेक्टर ने कहा युवा उत्सव प्रतिभाओं को निखारने और लोक संस्कृति के संरक्षण का

लोकनृत्य, लोकगीत, चित्रकला, कविता लेखन और नुक्कड़ नाटक सहित विभिन्न विधाओं में प्रतिभागियों ने दिखाई प्रतिभा

एक सत बुलेटिन ➤ गौरेला पेंड्रा मरवाही

जिले की समृद्ध लोक संस्कृति, पारंपरिक कला और युवाओं की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मल्टीपरपस स्कूल पेण्ड्रा के असेंबली हॉल में जिला स्तरीय युवा उत्सव 2026 का आयोजन किया गया। उत्सव में लोकनृत्य, लोकगीत, चित्रकला, कविता लेखन, नुक्कड़ नाटक, क्रिएटिव यूथ रील चैलेंज एवं पारंपरिक वेशभूषा सहित विभिन्न विधाओं में प्रतिभागियों ने अपनी कला, संस्कृति और सृजनशीलता का शानदार प्रदर्शन किया। पारंपरिक लोकगीतों की मधुर धुनों, लोकनृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियों और रंग-बिरंगी वेशभूषा ने आयोजन को सांस्कृतिक उत्सव का स्वरूप प्रदान किया। कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने युवा प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि युवा उत्सव जैसे आयोजन युवाओं की छिपी प्रतिभाओं को निखारने, उन्हें अपनी कला प्रदर्शित करने और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जनजाति बहुल जिला है। यहां की लोककला, लोकनृत्य, लोकगीत और परंपराएं हमारी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर हैं। इनका संरक्षण एवं संवर्धन करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने



युवाओं से अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने तथा इन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने जिले की गौरवशाली साहित्यिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह महान साहित्यकार एवं पत्रकारिता के पुरोधा पंडित माधवराव सप्रे की पावन कर्मभूमि है। इस धरती की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। युवाओं को इस गौरवशाली विरासत से प्रेरणा लेकर साहित्य, कला और रचनात्मक गतिविधियों में अपनी पहचान बनानी चाहिए।

कलेक्टर ने विशेष रूप से नुक्कड़ नाटक को जनजागरूकता का प्रभावी माध्यम बताते हुए युवाओं से नशामुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने उत्सव में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। युवा उत्सव में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। लोकनृत्य प्रतियोगिता में लमना के गौरा-गौरी नृत्य दल ने प्रथम तथा सैला नृत्य दल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। लोकगीत प्रतियोगिता में कल्याणी एवं साथी प्रथम तथा निष्ठा एवं साथी द्वितीय स्थान पर रहे।

इसी प्रकार चित्रकला प्रतियोगिता में अभिजीत चौधरी ने प्रथम एवं हरनाम सिंह पैकरा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कविता लेखन में योगिता रानी प्रथम तथा पूजा चौधरी द्वितीय स्थान पर रहीं। नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में बिहार समूह ने प्रथम एवं डाइट पेण्ड्रा ने द्वितीय स्थान हासिल किया। क्रिएटिव यूथ रील चैलेंज में श्याम गुप्ता समूह ने प्रथम एवं मानवी मिश्रा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिता में ईशांत रजक प्रथम एवं सुची कौल द्वितीय स्थान पर रहे। युवा उत्सव के माध्यम से जिले के युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ ही स्थानीय लोक संस्कृति, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर मिला। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद पेण्ड्रा के अध्यक्ष श्री राकेश जालान सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में प्रतिभागी उपस्थित रहे।

अब लड़ाई में सिर्फ लड़ाकू विमान-मिसाइल ही नहीं,

भविष्य की जंग में तकनीक मायने रखेगी: बोले रक्षा मंत्री राजनाथ



दो दिन चलेगा एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस

इस दो दिवसीय सम्मेलन में वायुसेना के सभी कमांड के एयर ऑफिसर्स कमांडिंग-इन-चीफ, वरिष्ठ अधिकारी और डायरेक्टर जनरल शामिल हो रहे हैं। इस साल सम्मेलन की थीम 'द ईयर ऑफ एम्पावरमेंट- मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन' रखी गई है। इसमें ऑपरेशन, रखरखाव और प्रशासन से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है।

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

अब लड़ाई में सिर्फ लड़ाकू विमान-मिसाइल ही नहीं, बल्कि ड्रोन, ढ्ढ, साइबर, तकनीक अहम भूमिका निभा रही हैं। इसी को देखते हुए राजनाथ सिंह ने वायुसेना को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रहने का संदेश दिया है।युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब जंग सिर्फ लड़ाकू विमानों, टैंकों और सैनिकों की संख्या के दम पर नहीं जीती जाती, बल्कि ड्रोन, मिसाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर तकनीक और सटीक रणनीति भी जीत तय करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर इजराइल-हमास संघर्ष तक, दुनिया ने आधुनिक युद्ध के कई नए रूप देखे हैं। ऐसे में भारत भी अपनी सैन्य ताकत को भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से तैयार करने में जुटा है।इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के कमांडरों को भविष्य के युद्ध की चुनौतियों को लेकर खास संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जीत सिर्फ लड़ाकू विमानों की संख्या से तय नहीं होगी, बल्कि तकनीक की ताकत, तेजी से जवाब देने की क्षमता और सटीक रणनीति सबसे अहम होगी। उन्होंने सेना को आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताएं मजबूत करने की सलाह दी। राजनाथ सिंह 12 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।

ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम पर खास जोर

रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध और इजराइल-हमास संघर्ष ने दिखा दिया है कि आधुनिक युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब जंग सिर्फ जमीन, आसमान और समुद्र तक सीमित नहीं है। मिसाइल, ड्रोन और आधुनिक हथियार युद्ध का अहम हिस्सा बन चुके हैं।

इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर बनेगी नई रणनीति

राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य के युद्ध में साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। इसलिए भारतीय वायुसेना को इन नए क्षेत्रों के लिए अलग से रणनीति और तकनीकी ढांचा तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खुफिया जानकारी और निगरानी तंत्र को मजबूत करना भी जरूरी है।

न्यूज इन शॉर्ट

अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी पर हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल



नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, तो तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को ‘-प्लस सिक्योरिटी मिलती थी। राज्य में सरकार बदलने के बाद उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई और घर के सामने लगातार पहरा देने वाले पुलिसवालों को भी हटा दिया गया। अभिषेक बनर्जी ने सिक्योरिटी में कमी का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उस मामले में सिक्योरिटी की समीक्षा पर सवाल उठाए और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।अभिषेक बनर्जी के घर के सामने से अस्थायी निर्माण हटाने का काम गुरुवार सुबह से शुरू हो गया। अभिषेक बनर्जी के वकील ने गुरुवार को सुनवाई में उस मुद्दे का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाए कि केस लंबित होने केअभिषेक की सुरक्षा की समीक्षा क्यों नहीं सिरे से सिक्योरिटी रिव्यू क्यों नहीं किय।

सैम पित्रोदा ने की मोदी की तारीफ, प्रधानमंत्री ने जवाब में दी दिवाली की शुभकामनाएं



नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी को दयालु, स्नेही और मेहनती बताया है। पित्रोदा ने कहा कि उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, लेकिन विचारधारा से असहमति है। इस पर पीएम ने पित्रोदा को जवाब दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने मोदी को दयालु, स्नेही, मेहनती और अच्छा वक्ता बताया। पित्रोदा ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं और उनके मन में मोदी के प्रति कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। उनके इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने उन्हें और उनके परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी का एक व्यक्ति के तौर पर सम्मान करते हैं। उन्होंने बताया कि वह कई बार मोदी से मिल चुके हैं और गुजरात में उनके घर भी जा चुके हैं।



सीईसी ज्ञानेश कुमार के पुराने मामले में बढ़ी हलचल, 20 साल बाद एक और गवाह ने खोले राज!

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

सीईसी ज्ञानेश कुमार से जुड़े केरलम के करीब 20 साल पुराने सड़क परियोजना मामले में जांच ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। VACB ने एक और गवाह शाहजहां का बयान दर्ज किया है।चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार एक बार फिर चर्चा में हैं। केरलम में लोक निर्माण विभाग के सचिव रहते हुए उनके कार्यकाल में शुरू हुई एक सड़क परियोजना में कथित भ्रष्टाचार की जांच तेज होती दिखाई दे रही है। इस मामले में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अब एक और गवाह का बयान दर्ज किया है। यह गवाह उस समय परियोजना में काम करने वाले मलेशियाई इंजीनियरों के साथ जुड़ा हुआ था।यह मामला करीब 20 साल पुराना है। जिस सड़क परियोजना को लेकर जांच हो रही है, उसकी शुरुआत साल 2006 में हुई थी। उस समय ज्ञानेश कुमार केरलम में लोक निर्माण विभाग के सचिव थे। परियोजना के तहत अंगमाली से तिरुवनंतपुरम तक एमसी रोड के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण किया जाना था। इसके लिए वर्ल्ड बैंक से 215 करोड़ रुपये की मदद ली गई थी। अब इतने साल बाद इस मामले में नए गवाहों के बयान और पुराने दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। गवाह का बयान दर्ज किया है।

यूपी में चंद्रशेखर-ओवैसी की पार्टियों में

सभी 403 सीटों पर लड़ेंगे, चंद्रशेखर सीएम फेस

एजेंसी ➤ लखनऊ

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन का ऐलान किया है। इसका नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा रखा गया है। गठबंधन यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा।गुरुवार को लखनऊ में संयुक्त प्रेसवार्ता में ओवैसी ने कहा





कि चंद्रशेखर यूपी में सीएम का चेहरा होंगे। भाजपा को रोकने के लिए हमारा मोर्चा मजबूत विकल्प बनेगा।सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि यह तीसरा मोर्चा नहीं, बल्कि पहला मजबूत मोर्चा होगा। बड़े गठबंधन में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन हमें कमजोर समझा गया।यूपी में मुस्लिम आबादी 19त्न और दलित आबादी 21त्न है। गठबंधन की नजर इसी 40त्न आबादी के वोटों पर है।

मोदी ने सुनाया किस्सा- आप गुजरात के सीएम बन रहे

जब मोदी को पत्रकारों से मिली ये खबर, दिवाली मिलन में पीएम ने सुनाया किस्सा

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों के साथ दीपावली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों और उनके परिवारों को दीपावली और छठ पर्व की शुभकामनाएं दीं। पत्रकारों की व्यस्त दिनचर्या का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि त्योहारों के समय हर कोई अपने परिवार और अपनों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करता है, लेकिन पत्रकारों की जिंदगी में ब्रेकिंग न्यूज के लिए लगातार भागदौड़ लगी रहती है।पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, 'अभी-अभी दीपावली का भी तैयारी अंतिम दौर पर है।

भाजपा प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी का छत्तीसगढ़ दौरा, रायगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस की करेंगी समीक्षा



संवाददाता ➤ रायपुर

रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रही है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भाजपा प्रदेश प्रभारी ईरानी रायपुर पहुंचेंगी, वहां से वे सीधे धरमजयगढ़ के लिए रवाना होंगी। धरमजयगढ़ में जनजातीय कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ ही पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी।15 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का रायगढ़ में कार्यक्रम है।भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन शामिल होंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर चल रही तैयारी के मद्देनजर भाजपा प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगी, साथ ही कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक बैठक भी लेंगी।स्मृति ईरानी विभिन्न संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगी।

भारत में शादी, विदेश में तलाकज्ज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी मान्यता, अब पति पर चलेगा केस

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

विदेश में तलाक लेकर दूसरी शादी करना एक भारतीय शख्स को भारी पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि भारत में हुई शादी को विदेशी अदालत से तलाक मिलने भर से खत्म नहीं माना जा सकता।

शादी भारत में हुई, पति-पत्नी के बीच रिश्ते बिगड़े और फिर दोनों में से कोई एक विदेश की अदालत पहुंच गया। वहां के कानून के आधार पर तलाक मिल गया और व्यक्ति ने दूसरी शादी भी कर ली। क्या ऐसे में भारत में भी पहली शादी खत्म मानी जाएगी? क्या विदेश की अदालत से मिला तलाक भारतीय कानून से बचने का रास्ता बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इन सवालों पर एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि ऐसा करना आसान नहीं होगा।

दुनिया में बढ़ता ब्रह्मोस का दबदबा,1400 ट्रक कचरा साफ, 11 किमी में घाट तैयार

छठ पर दिल्ली को बड़ा तोहफा, बदली मुनक नहर की तस्वीर

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

दिल्ली में छठ महापर्व के अवसर पर 11 किलोमीटर लंबा भव्य छठ घाट मुनक नहर पर तैयार किया गया है। 12 नवंबर को भाजपा अध्यक्ष इसका उद्घाटन करेंगे। छठ महापर्व के अवसर पर दिल्ली को 11 किलोमीटर लंबे भव्य छठ घाट की सौगात मिलने जा रही है। शालीमार बाग स्थित मुनक नहर के दोनों किनारों पर विकसित किए गए इस घाट का 12 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उद्घाटन करेंगे। सिंगलपुर गांव के पास लेबर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे।दिल्ली सरकार के मुताबिक, यह राजधानी का सबसे लंबा छठ घाट होगा।



श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का इंतजाम

छठ व्रतियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नहर के दोनों किनारों पर पक्की सीढ़ियां और सीमेंट की सड़कें बनाई गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम, शौचालय, टेंट, रोशनी और सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जा रही है। बैठने के लिए बेंच लगाने और आसपास हरियाली विकसित करने की भी योजना है। नहर में स्वच्छ पानी के प्रवाह के साथ अलग-अलग स्थानों पर फव्वारे लगाए जाएंगे।

न्यूज इन शॉर्ट

कलेक्टर जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनी आमजनों की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने गुरुवार को समय-सीमा की बैठक के बाद कलेक्टर जनदर्शन में आम नागरिकों की समस्याएं और मांगें सुनीं। जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों ने व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याओं से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने आवेदकों की बात सुनकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में भूमि संबंधी मामले में आवेदक रामकुमार ने पुराने नक्शे के आधार पर भूमि का नक्शा सुधारने और सीमांकन कराने की मांग की। ग्राम कलमी की आवेदिका मालती ने आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। उन्होंने आवेदन में कहा कि अपात्र अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई और पात्र अभ्यर्थी को अवसर से वंचित किया गया। उन्होंने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय समिति से जांच कराने का आग्रह किया।

ग्राम दनसरा में समलाई एवं जगन्नाथ मंदिर चौक पर शेड निर्माण कराने तथा ग्राम अमेठी में अवैध कब्जा हटाने की मांग से जुड़े आवेदन भी प्रस्तुत किए गए। धुमाभाठा निवासी ईश्वर प्रसाद ने आरबीसी 6-4 के तहत आर्थिक सहायता दिलाने का अनुरोध किया। अन्य आवेदनों में शौचालय निर्माण, ग्राम बसीनपाली के निवासियों को वन अधिकार पट्टा दिलाने और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पिछले तीन वर्षों से लंबित राशि का भुगतान कराने की मांग शामिल रही। जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों को आवश्यक जांच और परीक्षण कर पात्रतानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवेदनों के निराकरण में लापरवाही न हो और प्रत्येक प्रकरण पर नियमानुसार कार्रवाई कर आवेदकों को समय पर जानकारी दी जाए।

1 दिसंबर से बेमेतरा में चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध निर्माण पर भी होगी सख्त कार्रवाई

बेमेतरा। शहर को व्यवस्थित, स्वच्छ एवं सुंदर बनाने तथा यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद बेमेतरा द्वारा 1 दिसंबर से व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत शहर के प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अभियान के अंतर्गत सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण, दुकानों के सामने सार्वजनिक स्थानों पर किए गए कब्जे तथा आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाले अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा। नगर पालिका का उद्देश्य आम नागरिकों को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना और शहर की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करना है।



बिना अनुमति निर्माण करने वालों पर भी होगी कार्रवाई नगर पालिका क्षेत्र में भवन निर्माण को लेकर भी प्रशासन सख्ती बरतने जा रहा है। जिन भवन मालिकों ने बिना भवन अनुज्ञा (परमिशन) के निर्माण कराया है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों ने आवासीय भवन निर्माण की अनुमति लेकर उसका व्यावसायिक उपयोग अथवा व्यावसायिक निर्माण किया है, ऐसे मामलों की भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा ने शहरवासियों एवं व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अभी तक अपने भवन निर्माण की अनुमति नहीं ली है, वे नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर नियमानुसार भवन अनुज्ञा प्राप्त करें। वहीं जिन लोगों ने स्वीकृत नक्शे एवं अनुमति की शर्तों के विपरीत निर्माण किया है, वे भी अपने दस्तावेजों की जांच कराकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।

नगर पालिका सीएमओ की कार्यशैली आगामी चुनाव में भाजपा के लिए बन सकती है राजनीतिक नुकसान का कारण

नालियां जाम, गाजर घास की सफाई नदारद, गैस पाइपलाइन जस के तस; छह महीने से दूषित पानी की शिकायतें भी बेअसर

एक सत बुलेटिन ➤ कोरिया

नगर पालिका परिषद में भाजपा की सरकार होने के बावजूद शहर की बदहाल स्थिति अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष नविता शिवहरे और भाजपा के पार्षद लगातार जनता के बीच जवाबदेह हैं, लेकिन शहर की बुनियादी समस्याओं का निराकरण नहीं होने से आम नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है। सबसे बड़ा सवाल नगर पालिका के प्रशासनिक कामकाज और मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) की कार्यशैली को लेकर खड़ा हो रहा है।

शहर की स्थिति पर नजर डालें तो बरसात से पहले से ही नालियों की नियमित सफाई नहीं होने, नालियों के जाम रहने और सड़कों के किनारे गाजर घास की सफाई नहीं किए जाने जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। अब लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भी शहर में जिस स्तर की साफ-सफाई और व्यवस्थाएं होनी चाहिए थीं, उनका अभाव दिखाई दे रहा है। दीपावली जैसे बड़े त्योहार के दौरान भी शहर की सफाई



व्यवस्था अपेक्षित स्तर पर नजर नहीं आई। छह महीने से दूषित पेयजल की शिकायत, फिर भी समाधान नहीं!

शहर की एक और गंभीर समस्या कई वार्डों में दूषित पेयजल की आपूर्ति को लेकर सामने आ



रही है। स्थानीय नागरिकों द्वारा पिछले लगभग छह महीनों से पेयजल की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें की जा रही हैं। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना नगर पालिका की प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल है। ऐसे में लंबे समय से चली आ रही इस समस्या का निराकरण नहीं होना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी अब तक ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाए हैं?

गैस पाइपलाइन के गड्ढों से परेशान शहरवासी

सबसे गंभीर स्थिति उन वार्डों की है, जहां गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क और गलियों में गड्ढे खोदे गए थे। लंबे समय बीत जाने के बावजूद इन गड्ढों को व्यवस्थित तरीके से भरा नहीं गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बार-बार इस समस्या को उठाया गया। नगर पालिका अधिकारियों की ओर से आश्वासन भी दिए गए, लेकिन धरातल पर समस्या जस की तस बनी हुई है। शहर की सड़कें और गलियां जगह-जगह अव्यवस्थित नजर आ रही हैं, जिससे आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है।

भाजपा की नगर सरकार, लेकिन जनता के सामने जवाबदेही किसकी?

यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब नगर पालिका में अध्यक्ष और पार्षद भाजपा के हैं, तो आखिर उनके द्वारा उठाई जा रही समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? नगर पालिका के प्रशासनिक संचालन, अधिकारियों-कर्मचारियों से काम लेने और योजनाओं को जमीन पर उतारने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होती है। ऐसे में यदि जनप्रतिनिधियों के निर्देशों और बार-बार दिए गए सुझावों के बावजूद काम नहीं हो रहे हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही तय होनी चाहिए। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल भी उठ रहा है कि कहीं प्रशासनिक निष्क्रियता का खामियाजा भाजपा की निर्वाचित नगर सरकार को तो नहीं भुगतना पड़ रहा है? यदि अध्यक्ष और पार्षद जनता की समस्याओं का समाधान कराने में असहाय दिखाई देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जनता के बीच उनकी कार्यक्षमता पर सवाल उठेंगे।

इसलिए विभागीय परीक्षा एवं योग्यता के आधार पर कैडर पुनर्गठन करते हुए पदोन्नति की उचित व्यवस्था की जाए

पांच सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रावास अधीक्षकों का प्रदेशव्यापी सांकेतिक हड़ताल एवं धरना-प्रदर्शन, कर्मचारी संगठनों ने दिया समर्थन

एक सत बुलेटिन ➤ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आज जिले के छात्रावास अधीक्षकों द्वारा अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल एवं धरना-प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अधीक्षकों ने अपनी सेवा संबंधी समस्याओं एवं छात्रावास संचालन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को प्रमुखता से उठाया। संघ की पांच प्रमुख मांगों में छात्रावास अधीक्षकों के कार्य समय एवं अवकाश का निर्धारण, अधीक्षक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन एवं विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति का अवसर, शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को उपस्थिति प्रणाली से छूट, एवं ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली की व्यावहारिक समस्याओं का निराकरण तथा छात्रावास संचालन के लिए पर्याप्त एवं मदवार बजट उपलब्ध कराना शामिल है। संघ का कहना है कि छात्रावास अधीक्षक का पद सामान्य कार्यालयीन पद नहीं है, बल्कि इसमें 24 घंटे विद्यार्थियों की देखरेख एवं सुरक्षा



की जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। अधीक्षकों को दिन-रात छात्रावास में उपस्थित रहकर विद्यार्थियों की भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है। विशेषकर महिला अधीक्षिकाओं के लिए यह व्यवस्था अत्यंत कठिन है। उन्हें अपने पदस्थापना स्थल पर छात्रावास परिसर में रहना पड़ता है, जिसके कारण कई बार वे अपने पति एवं परिवार के साथ सामान्य पारिवारिक जीवन नहीं बिता पातीं। 24 घंटे की ड्यूटी और अवकाश की अनिश्चितता के बीच बच्चों की परवरिश, बुजुर्गों की देखभाल तथा अन्य पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। संघ की मांग है कि अधीक्षकों के लिए निर्धारित कार्य अवधि, साप्ताहिक अवकाश एवं शासकीय अवकाश की स्पष्ट व्यवस्था बनाई जाए। इसी प्रकार अधीक्षक संवर्ग में भर्ती होकर पूरी सेवावधि एक ही पद पर कार्य करते हुए उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाना कर्मचारियों के साथ अन्यायपूर्ण स्थिति है। वर्षों की सेवा, अनुभव एवं जिम्मेदारियों के बावजूद पदोन्नति के अवसर नहीं मिलना कर्मचारियों के मनोबल को प्रभावित करता है। इसलिए विभागीय परीक्षा एवं योग्यता के आधार पर कैडर पुनर्गठन करते हुए पदोन्नति की उचित व्यवस्था की जाए।

इसके अतिरिक्त शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को ड्यूल्य उपस्थिति प्रणाली से छूट देने, ॥स्व- पोर्टल की तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने तथा न्यूनतम 24 दिवस की उपस्थिति पर पूरे माह का मेस बजट उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। छात्रावासों में विद्यार्थियों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त एवं मदवार बजट उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

भटगांव सिंघिचुवा रोड में दर्दनाक सड़क हादसा, मिक्सर मशीन पलटने से मजदूर की दबकर मौत

मिक्सर मशीन में सवार अन्य मजदूर और चालक घटना के बाद फरार



भटगांव, नगर पंचायत भटगांव में तड़के सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। सिंघिचुआ मार्ग पर एक मिक्सर मशीन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मिक्सर मशीन सड़क किनारे पलट गई और लोहे के खम्बे भी मुड़ गई. हादसे में मशीन में सवार एक मजदूर की दबकर मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान भोला साहू के रूप में हुई है, जो नकटीडीह गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, भोला साहू मिक्सर मशीन में सवार होकर ढलाई कार्य के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही भटगांव पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुट गई। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद मिक्सर मशीन में सवार अन्य मजदूर और चालक मौके पर मौजूद नहीं मिले। हालांकि, वे घायल हुए हैं या सुरक्षित हैं, इसकी फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई प्रतियां

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की जिला स्तरीय बैठक आयोजित

एक सत बुलेटिन ➤ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के अंतर्गत अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के आधार पर तैयार मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन जिले के सभी मतदान केंद्रों एवं निर्धारित स्थानों पर किया गया है। इस संबंध में आज जिला निर्वाचन कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 24-मरवाही एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 25-कोटा के अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 01 से 70 तक की



फोटोयुक्त मतदाता सूची की एक-एक मुद्रित प्रति तथा फोटो रहित मतदाता सूची की सॉफ्टकॉपी सीडी के माध्यम से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन एवं संशोधन से संबंधित प्रपत्र 6, 7 एवं 8 तथा दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा बताया गया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का उद्देश्य निर्वाचक नामावली को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है, ताकि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सकें। इस कार्य में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सहभागिता भी महत्वपूर्ण है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

जिला स्तरीय आकलन शिविर में 97 दिव्यांग बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, 17 सहायक उपकरणों के लिए चयनित



मेडिकल बोर्ड ने किया दिव्यांग परीक्षण, प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड बनाने और नवीनीकरण की हुई कार्रवाई

एक सत बुलेटिन ➤ एमसीबी

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला स्तरीय आकलन शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक के निर्देशानुसार समग्र शिक्षा विभाग द्वारा 5 नवम्बर को विकासखंड स्रोत केंद्र मनेन्द्रगढ़ में आयोजित शिविर में जिले के तीनों विकासखंडों के कुल 97 दिव्यांग बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं आकलन किया गया। इनमें से 17 बच्चों का चयन विभिन्न सहायक उपकरणों के लिए किया गया, जिन्हें आगामी दिसम्बर माह में आयोजित वितरण शिविर में उपकरण प्रदान किए जाएंगे।

तीनों विकासखंडों के 97 बच्चों का हुआ परीक्षण

शिविर में कक्षा पहली से बारहवीं तक अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन एवं उनकी आवश्यकताओं का आकलन किया गया। विकासखंड मनेन्द्रगढ़ में निर्धारित 70 बच्चों के लक्ष्य के विरुद्ध 55, भरतपुर में 24 के विरुद्ध 16 तथा खड़गवां में 37 के विरुद्ध 26 बच्चों का परीक्षण किया गया। इस प्रकार जिले में कुल 131 बच्चों के लक्ष्य के विरुद्ध 97 बच्चों का आकलन किया गया। एलिम्को रायपुर की विशेषज्ञ टीम ने बच्चों की दिव्यांग एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर सहायक उपकरणों के लिए 17 बच्चों का चयन किया।

दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड के लिए हुई कार्रवाई

शिविर में जिला मेडिकल बोर्ड के चिकित्सकों ने श्रवण बाधित, अस्थिबाधित, बौद्धिक दिव्यांग, दृष्टिबाधित एवं बहु दिव्यांग बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान पात्र बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र बनाने तथा नवीनीकरण की कार्रवाई की गई। शिविर का उद्देश्य बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की पहचान कर उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना और शिक्षा में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना रहा। अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की रही उपस्थिति कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड क्रमांक 18 के पार्षद अनिल प्रजापति उपस्थित रहे। जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा कोरिया/एमसीबी अरविन्द कुमार सिंह, विकासखंड शिक्षा अधिकारी मनेन्द्रगढ़ विपिन कुमार पाण्डेय, विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक अलका चौहथा, एपीसी समावेशी शिक्षा गौरी शंकर ऐडे तथा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनेन्द्रगढ़ के प्राचार्यों ने शिविर के संचालन में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया।

प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन, दावा-आपत्ति एवं मतदाता जागरूकता अभियान के संबंध में दी गई विस्तृत जानकारी

कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े की अध्यक्षतां में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 को लेकर बैठक हुई सम्पन्न

एक सत बुलेटिन ➤ एमसीबी

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (स्स्क्र)-2027 को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 के आधार पर निर्वाचक नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन, दावा-आपत्ति, नए मतदाताओं के पंजीयन एवं आगामी निर्वाचन संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी गई।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी लिंगराज सिदार, अनुविभागीय अधिकारी एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 02 मनेंद्रगढ़ के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शशि शेखर मिश्रा सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आशीष सिंह भारतीय जनता पार्टी, रफीक मेमन इंडियन नेशनल कांग्रेस, विशेष सोनी आम आदमी पार्टी, हरिशंकर ताजेन बहुजन समाज पार्टी से और पर्यवेक्षक सतीश द्विवेदी एवं सहायक प्रोग्रामर उपेंद्र कुमार जिला निर्वाचन कार्यालय से उपस्थित रहे।

जिले में 2 लाख 97 हजार 880 मतदाता पंजीकृत

कलेक्टर ने बताया कि आज से जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 01 भरतपुर-सोनहत एवं 02 मनेंद्रगढ़ की



प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन सभी निर्धारित मतदान केंद्रों एवं स्थलों पर किया गया है। प्रारंभिक सूची के अनुसार जिले में कुल 2,97,880 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 1,48,627 पुरुष, 1,49,247 महिला एवं 06 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र में 1,74,230 तथा मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1,23,650 मतदाता दर्ज हैं। जिले में कुल 503 मतदान केंद्र हैं, जिनमें भरतपुर-सोनहत में 322 तथा मनेंद्रगढ़ में 181 मतदान केंद्र शामिल हैं।

पुनरीक्षण अभियान के तहत युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिले में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 3,195 नए युवा मतदाता पंजीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त जिले में 874 वरिष्ठ नागरिक, 3,670 दिव्यांग मतदाता तथा 304 सेवा निर्वाचक पंजीकृत हैं।

12 नवंबर से 11 दिसंबर तक लिए जाएंगे दावा-आपत्ति

कलेक्टर ने बताया कि प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावा एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त आवेदनों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 04 जनवरी 2027 को होगा। पात्र नागरिक, जो 01 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप-06, नाम विलोपन के लिए प्रारूप-07 तथा नाम, पता एवं अन्य विवरणों में संशोधन अथवा स्थानांतरण के लिए प्रारूप-08 में आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आगामी अर्हता तिथियों 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं के अग्रिम आवेदन भी प्राप्त किए जा रहे हैं। मतदाता अपना नाम जांचने, नया पंजीयन कराने अथवा संशोधन एवं स्थानांतरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल तथा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुनरीक्षण संबंधी जानकारी एवं दावा-आपत्तियों की सूची जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। बीएलए की नियुक्ति एवं मतदाता जागरूकता पर जोर कलेक्टर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट (ब्ल्क्र) की नियुक्ति शीघ्र सुनिश्चित करने तथा मतदाता जागरूकता अभियान में सक्रिय सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीएलए एवं बूथ लेवल अधिकारियों के समन्वय से पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और मतदाता सूची की त्रुटियों को सुधारने में मदद मिलेगी।

न्यूज इन शॉर्ट

किसान साफ और सूखा धान लेकर पहुंचें उपार्जन केंद्र, नमी की अधिकतम सीमा 17 प्रतिशत

सारंगढ़-बिलाईगढ़। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। सारंगढ़ विकासखंड के 30, बरमकेला के 27 और बिलाईगढ़ के 38 सहित जिले के कुल 95 उपार्जन केंद्रों में किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने धान उपार्जन के लिए गुणवत्ता और तौल संबंधी मानक निर्धारित किए हैं। कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप साफ और सूखा धान ही केंद्रों में लेकर आएं, ताकि खरीदी प्रक्रिया सुगमता और पारदर्शिता के साथ पूरी हो सके। विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार धान में नमी की अधिकतम मात्रा 17 प्रतिशत होनी चाहिए। धान में अकार्बनिक और कार्बनिक विजातीय पदार्थों की अधिकतम सीमा अलग-अलग एक-एक प्रतिशत निर्धारित की गई है। अपरिपक्व, सिकुड़े और छोटे दानों की अधिकतम सीमा तीन प्रतिशत तथा निम्न श्रेणी के धान के मिश्रण की सीमा छह प्रतिशत रखी गई है। क्षतिग्रस्त, अंकुरित और चुने हुए दाने चार प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। किसानों से धान की खरीदी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। खरीदी केंद्रों में तौल के दौरान प्रति बोरा धान की मात्रा 40 किलोग्राम रहेगी। नए जूट बारदाने का वजन 545 ग्राम से 626 ग्राम तक निर्धारित है। किसानों से आग्रह किया गया है कि वे केंद्र में धान लाने से पहले उसकी अच्छी तरह सफाई और सुखाई कर लें तथा तौल के समय धान की मात्रा और बारदाने के वजन पर ध्यान दें। इससे उपार्जन केंद्रों में धान विक्रय की प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से पूरी हो सकेगी।

`तुंहर टोकन' मोबाइल ऐप से धान खरीदी होगी सरल और पारदर्शी

किसान घर बैठे ले सकेंगे टोकन, रकबे के अनुसार टोकन की संख्या तय

टोकन नियमों का पालन सुनिश्चित करने अधिकारियों को कलेक्टर के निर्देश

सारंगढ़-बिलाईगढ़। राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया को सहज, सरल और पारदर्शी बनाने के लिए 'तुंहर टोकन' मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। ऐप के माध्यम से किसान धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे। शासन ने टोकन जारी करने, खरीदी की मात्रा तय करने और खरीदी की तारीख चुनने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने तथा किसानों को ऐप और टोकन प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
शासन के निर्देशों के अनुसार किसान के पंजीकृत रकबे के आधार पर टोकन की अधिकतम संख्या तय की गई है। दो एकड़ तक रकबा रखने वाले सीमांत किसानों को अधिकतम एक टोकन, दो एकड़ से अधिक और दस एकड़ तक रकबा रखने वाले लघु किसानों को अधिकतम दो टोकन तथा दस एकड़ से अधिक रकबा रखने वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन जारी किए जा सकेंगे। किसान को जारी सभी टोकनों में दर्ज धान की कुल मात्रा उसकी पात्र खरीदी मात्रा के बराबर या उससे कम होना अनिवार्य है। टोकन में धान की मात्रा दर्ज करते समय प्रति बोरा अनुमानित 0.40 क्विंटल के मान से प्रविष्टि करना भी जरूरी होगा। 'तुंहर टोकन' ऐप के माध्यम से सोमवार से शुक्रवार तक 24 घंटे टोकन बनाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। टोकन में धान तौल की तारीख उसी दिन की नहीं रखी जा सकेगी। शनिवार, रविवार और घोषित शासकीय अवकाश के दिन तौल की तारीख चुनने की अनुमति नहीं होगी। किसान का बैंक खाता सत्यापित होना जरूरी है; असत्यापित बैंक खाते वाले किसान को टोकन जारी नहीं किया जाएगा। एक किसान के नाम पर एक ही दिन में दो से अधिक टोकन जारी नहीं किए जा सकेंगे। पहले जारी टोकन में संशोधन या उसे निरस्त करने की कार्रवाई संबंधित समिति के माध्यम से की जाएगी। निरस्त टोकन को छोड़कर शेष टोकनों में दर्ज धान की मात्रा के आधार पर खरीदी की पात्र मात्रा की गणना होगी। टोकन के लिए आवेदन खरीदी अवधि के दौरान किया जा सकेगा और टोकन जारी करने की सुविधा धान खरीदी के अंतिम दिन तक उपलब्ध रहेगी।

निःशुल्क कानूनी सहायता से लेकर साइबर ठगी, पॉक्सो एक्ट और नशामुक्ति तक किया गया जागरूक

परसगढ़ी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, ग्रामीणों को दी गई कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी

एक सत बुलेटिन ➤ एमसीबी

एमसीबी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत परसगढ़ी में विधिक साक्षरता एवं जनजागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1318 के परिपालन में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता और शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना रहा।कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यस्थता से संबंधित बैनर लगाकर ग्रामीणों को कानून की बारीकियों और जरूरतमंद लोगों को



मिलने वाली कानूनी सुविधाओं की जानकारी दी गई। ग्राम पंचायत परसगढ़ी के सरपंच की अगुवाई में अधिकार मित्र अजय विश्वकर्मा, थाना मनेंद्रगढ़ एवं थाना झगराखांड की संयुक्त सहभागिता से शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी



गई। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जरूरतमंदों एवं पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया समझाई गई। ग्रामीणों को बताया गया कि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आर्थिक अभाव के कारण न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी भी दी गई।इसके साथ ही महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा से जुड़े पॉक्सो अधिनियम, साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन ठगी के तरीकों और उससे सतर्क रहने के उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में परिवहन नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए राष्ट्रीय नशामुक्ति से संबंधित जानकारी भी साझा की गई। नशे की लत से होने वाले सामाजिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों को समझाते हुए नशामुक्ति हेल्पलाइन नंबर 14446 के बारे में बताया गया।

प्राथमिक शाला कछौड़ पहुंचीं कलेक्टर संतन देवी जांगड़े, बच्चों से संवाद कर जानी शैक्षणिक स्थिति

सात किलोमीटर दूर से विद्यालय आने वाले 18 बच्चों की ली जानकारी, नियमित उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर दिया जोर

एक सत बुलेटिन ➤ एमसीबी



कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े ने प्राथमिक शाला कछौड़ का आकस्मिक निरीक्षण कर विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से आत्मीयता के साथ बातचीत करते हुए उनकी पढ़ाई-लिखाई, विद्यालय में मिलने वाली सुविधाओं और भविष्य के सपनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने बच्चों से पूछा कि वे पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या बनना चाहते हैं। उन्होंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने, नियमित विद्यालय आने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करने हेतु प्रेरित किया।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यालय में अध्ययनरत ऐसे 18 बच्चों की विशेष रूप से जानकारी ली, जो लगभग सात किलोमीटर दूर से प्रतिदिन विद्यालय आते हैं। उन्होंने इन बच्चों के विद्यालय आने-जाने की स्थिति तथा उनकी नियमित उपस्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले बच्चों की शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता बताई।
कलेक्टर सुश्री जांगड़े ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। बच्चों की नियमित उपस्थिति, शैक्षणिक प्रगति और उनकी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है, इसलिए विद्यालय स्तर पर बच्चों की पढ़ाई के साथ उनके सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर लिंगराज सिदार एवं एसडीएम श्रीमती इंदिरा मिश्रा उपस्थित रहीं।

मनेन्द्रगढ़ वनमंडल में कथित करोड़ों के घोटाले को दबाने की कोशिश चिरमिरी भूजल संरक्षण कार्यों पर उठे सवाल, जांच की मांग तेज!

एसडीओ अवधेश सिंह की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप, कागजों में विकास और जमीन पर काम की हकीकत छिपाने का आरोप

एक सत बुलेटिन ➤ एमसीबी

मनेन्द्रगढ़ वनमंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र चिरमिरी में भूजल संरक्षण कार्यों को लेकर उठे कथित करोड़ों रुपये के घोटाले का मामला अब और गंभीर होता नजर आ रहा है। अप्रैल 2026 में स्वीकृत वित्तीय वर्ष 2026-27 की भूजल संरक्षण परियोजना में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठने के बाद अब यह चर्चा भी तेज हो गई है कि कहीं इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है?
जानकारी के अनुसार, चिरमिरी वन परिक्षेत्र में भूजल संरक्षण के तहत कंटूर निर्माण, बोल्डर चेकडैम, 9 नग परकुलेशन टैंक, मिनी परकुलेशन टैंक और तालाब निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य स्वीकृत किए गए थे। इन कार्यों का उद्देश्य जंगलों में वर्षा जल का संचयन, भूजल स्तर में वृद्धि और प्राकृतिक जलस्रोतों का संरक्षण करना था।
लेकिन अब इन कार्यों की वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि मनेन्द्रगढ़ फॉरेस्ट एसडीओ अवधेश सिंह के संरक्षण में कर्मचारियों पर दबाव बनाकर कथित फर्जी प्रमाणक और फर्जी मजदूरों की सूची तैयार कर भुगतान की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह सरकारी राशि के दुरुपयोग का गंभीर मामला होगा।
कागजों में लाखों-करोड़ों के काम, मौके पर



कहां हैं निर्माण?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन कार्यों के नाम पर सरकारी राशि स्वीकृत हुई, क्या वे सभी कार्य वास्तव में धरातल पर पूरे किए गए हैं? यदि तालाब और परकुलेशन टैंक बनाए गए हैं तो उनकी लोकेशन और निर्माण की तस्वीरें सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रहीं? मजदूरों के नाम पर भुगतान हुआ है तो संबंधित मजदूरों की वास्तविकता सामने क्यों नहीं लाई जा रही?

घोटाले के आरोपों के बाद अब मामले को दबाने की कोशिश?

मामले में अब एक और गंभीर सवाल उठ रहा है कि कथित अनियमितताओं की चर्चा सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारी पारदर्शिता के साथ जांच कराने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? आखिर किन परिस्थितियों में कार्यों के दस्तावेज, भुगतान और निर्माण की वास्तविक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं? क्या विभाग के उच्चाधिकारी इन शिकायतों को गंभीरता से ले रहे हैं या फिर जिम्मेदारों को बचाने का प्रयास



किया जा रहा है?

मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में मामला, अब क्या होगी कार्रवाई?

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग की इस परियोजना को लेकर उठ रहे सवाल शासन-प्रशासन के लिए भी चुनौती हैं। जनता जानना चाहती है कि क्या मंत्री इस मामले का संज्ञान लेकर उच्चस्तरीय जांच के निर्देश देंगे या फिर यह मामला भी विभागीय कार्रवाई के नाम पर फाइलों में दबकर रह जाएगा?

जांच हो, दस्तावेज सार्वजनिक हों और जिम्मेदारी तय हो!

इस पूरे मामले में वन विभाग के उच्चाधिकारियों से मांग है कि चिरमिरी वन परिक्षेत्र के भूजल संरक्षण कार्यों की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। स्वीकृत राशि, कार्यवार लागत, मस्टर रोल, मजदूरों की सूची, भुगतान विवरण और कार्य पूर्णता प्रमाणपत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाए।

टीबी मुक्त भारत अभियान में लायंस क्लब मनेन्द्रगढ़ की सराहनीय पहल, पोषण सहायता के लिए दिए 51 हजार रुपये

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे की पहल पर बढ़ा सामाजिक सहयोग, टीबी मरीजों को मिलेगा अतिरिक्त पोषण आहार

एक सत बुलेटिन ➤ एमसीबी

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में सामाजिक संस्थाएं भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। इसी कड़ी में लायंस क्लब मनेन्द्रगढ़ ने टीबी मरीजों को अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। क्लब द्वारा गुरुवार को यह राशि चेक के माध्यम से जिले के सहयोग कोष (चाइल्ड अकाउंट) में प्रदान की गई।



कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े के मार्गदर्शन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे की पहल पर जिले में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जनसहभागिता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, सहकारी समितियों, कॉर्पोरेट संस्थानों एवं गैर सरकारी संगठनों को निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों के उपचार के दौरान अतिरिक्त पोषण आहार एवं अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी पहल से प्रेरित होकर लायंस क्लब मनेन्द्रगढ़ ने आर्थिक सहयोग प्रदान कर सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया है।

टीबी उन्मूलन में सामुदायिक सहभागिता की महत्वपूर्ण भूमिका

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने बताया कि टीबी एक गंभीर संक्रामक बीमारी है, जिसका प्रभाव मरीजों के स्वास्थ्य के साथ उनकी आजीविका और दैनिक जीवन पर भी पड़ता है। उपचार के दौरान पर्याप्त पोषण आहार मिलने से मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार और उपचार की प्रभावशीलता बढ़ाने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों के साथ सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। अभियान का प्रमुख उद्देश्य उपचाररत टीबी मरीजों को सामुदायिक सहयोग से अतिरिक्त पोषण आहार एवं अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि मरीजों को उपचार अवधि में बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन परिस्थिति प्राप्त हो सकें।

निक्षय मित्र बनकर कोई भी व्यक्ति या संस्था कर सकती है सहयोग

डॉ. खरे ने बताया कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कोई भी व्यक्ति, सामाजिक संस्था, कॉर्पोरेट संगठन, जनप्रतिनिधि, पंचायती राज संस्था अथवा अन्य संगठन निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों की सहायता कर सकता है। इसके माध्यम से मरीजों को पोषण आहार सहित अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा सकता है।

मनेन्द्रगढ़ के विवेक तिवारी की पहल बनी प्रेरणा, आखिर कब समझेंगे लोग योग का महत्व

योग अपनाएं, जीवन बचाएंज स्वस्थ परिवार ही समृद्ध समाज की पहचान!

एक सत बुलेटिन ➤ मनेन्द्रगढ़

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान के पास हर चीज के लिए समय है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं। सुबह देर से उठना, अनियमित खानपान, शारीरिक मेहनत से दूरी और तनावपूर्ण जीवनशैली ने लोगों को बीमारियों की ओर धकेल दिया है। ऐसे दौर में योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
मनेन्द्रगढ़ के विवेक तिवारी योग के प्रति अपनी जीवनशैली और सोच के माध्यम से समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। उनका संदेश स्पष्ट है–योग को अपनाइए, स्वयं स्वस्थ रहिए और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित कीजिए।
सवाल यह है कि जब हम अपने परिवार के भविष्य, बच्चों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, तो फिर परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता क्यों नहीं देते? क्या परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी केवल पैसा कमाने तक



सीमित है? क्या स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से बढ़कर भी कोई संपत्ति हो सकती है?योग हमें अपने शरीर के प्रति जागरूक बनाता है। नियमित योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान से शारीरिक क्षमता, मानसिक शांति और जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा मिल सकता है। इसके लिए महंगे उपकरणों या बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं, बल्कि नियमित अभ्यास और दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।
विवेक तिवारी जैसे लोग समाज को यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि स्वास्थ्य की शुरुआत स्वयं से होती है। यदि परिवार का एक सदस्य योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करता है, तो वह पूरे परिवार के लिए प्रेरणा बन सकता है। यही छोटी-सी शुरुआत आगे चलकर स्वस्थ समाज की नींव बन सकती है। लेकिन केवल योग दिवस मनाने, तस्वीरें खिंचवाने और सोशल मीडिया पर संदेश साझा करने से समाज स्वस्थ नहीं होगा। जरूरत है योग को दिखावे से निकालकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की। स्कूलों, सामाजिक संगठनों और परिवारों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। हमारा सवाल समाज से है–जब स्वस्थ रहने का रास्ता हमारे सामने है, तो फिर हम अपनी सेहत के प्रति इतने लापरवाह क्यों हैं? आइए, आज संकल्प लें कि प्रतिदिन कुछ समय अपने शरीर और मन के लिए जरूर निकालेंगे। योग को अपनी आदत बनाएंगे और अपने बच्चों को भी स्वस्थ जीवनशैली का महत्व सिखाएंगे।
क्योंकि याद रखिए, बीमारी आने के बाद स्वास्थ्य की कीमत समझने से बेहतर है कि बीमारी से बचाव के लिए आज ही जागरूक हुआ जाए।

जिले के 23 उपार्जन केंद्रों में 15 नवंबर से होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, तैयारियां लगभग पूर्ण

जिले में 23 हजार 812 पंजीकृत किसान बेच सकेंगे धान

अवैध धान परिवहन एवं भंडारण रोकने सीमावर्ती क्षेत्रों में 23 चेकपोस्ट स्थापित

एक सत बुलेटिन ➤ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का कार्य 15 नवंबर से प्रारंभ किया जा रहा है। धान खरीदी 15 जनवरी 2027 तक की जाएगी। कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

तीन नए केंद्रों के साथ जिले में अब 23 धान उपार्जन केंद्र

किसानों की सुविधा और धान खरीदी व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष जिले में तीन नए धान उपार्जन केंद्र हर्राटोला, कोरजा एवं कुड़कई में स्थापित किए गए हैं। इन नवीन केंद्रों को मिलाकर जिले में धान उपार्जन केंद्रों की कुल संख्या 23 हो गई है। जिले के अन्य 20 उपार्जन केंद्रों में करगीकला, कोडगार, बस्ती, खोडरी, जोगीसार, गौरेला, तेंदूमूड़ा, तरईगांव, देवरीकला, धनौली, नवागांव, पेण्ड्रा, परासी, भरींडांड़, मेढुका, मरवाही, लरकेनी, लालपुर, निमधा एवं सिवनी शामिल हैं।
जिले में 23 हजार 812 किसान पंजीकृत खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए जिले में कुल 23 हजार 812 किसान पंजीकृत हैं। इनमें दो एकड़ तक भूमि वाले 10 हजार 573 सीमांत किसान, दो से दस एकड़ तक भूमि वाले 12 हजार 175 लघु किसान तथा दस एकड़ से अधिक भूमि वाले 10 64 बड़े किसान शामिल हैं। राज्य शासन के निर्णय अनुसार पंजीकृत किसान प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर विक्रय कर सकेंगे। इस वर्ष कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये तथा ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। तुम्हर टोकन एप से घर बैठे टोकन प्राप्त करने की सुविधा
राज्य शासन द्वारा किसानों की सुविधा के लिए %तुम्हर टोकन% एप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से किसान घर बैठे धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकते हैं। जिले में अब तक 11 उपार्जन केंद्रों के लिए 46 किसानों को एप के माध्यम से टोकन जारी किए गए हैं।

न्यूज इन शॉर्ट

6 हजार करोड़ के महादेव सट्टा सिंडिकेट में सौरभ चंद्राकर ने झाड़ा पल्ला, लाइजनिंग से किया इनकार

रायपुर। करीब छह हजार करोड़ रुपये के महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में गिरफ्तार मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ने पूछताछ के दौरान कई अहम जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। आठ दिन की रिमांड के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उससे सट्टा कारोबार के संचालन, हवाला के जरिये रकम के लेनदेन, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से कथित लाइजनिंग तथा नेटवर्क में शामिल लोगों की भूमिका को लेकर पूछताछ की।सूत्रों के अनुसार, सौरभ ने लाइजनिंग का काम खुद करने से इनकार करते हुए इसकी जिम्मेदारी रवि उप्पल पर होने की बात कही। वहीं, पैनल संचालन और हवाला लेनदेन की व्यवस्था संभालने की बात उसने स्वीकार की है।पूछताछ के दौरान सीबीआई ने शुभम सोनी की ओर से जारी उस वीडियो का भी हवाला दिया, जिसमें शुभम ने दावा किया था कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल उसके अधीन काम करते थे। इस पर सौरभ ने कथित तौर पर कहा कि इस संबंध में शुभम सोनी से ही पूछताछ की जानी चाहिए। इस तरह उसने वीडियो में किए गए दावों पर सीधे जवाब देने से बचने की कोशिश की। सीबीआई की पूछताछ में क्या-क्या सामने आया? सीबीआई की जांच का एक प्रमुख बिंदु यह पता लगाना था कि महादेव सट्टा नेटवर्क को छत्तीसगढ़ में किसका संरक्षण हासिल था और अवैध कमाई का हिस्सा किन लोगों तक पहुंचाया जाता था। जांच एजेंसी ने रिमांड के दौरान सौरभ से उसके सहयोगियों, पैनल संचालकों, हवाला कारोबारियों और कथित संरक्षण देने वाले अधिकारियों के संबंध में जानकारी जुटाने की कोशिश की।

छत्तीसगढ़ में माओवाद खत्म, लेकिन बीजापुर में अब भी जमीन के अंदर से निकल रहे बड़े बम

बीजापुर = जिले में माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और सुरक्षा बलों व आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने करकेली से बेदरे मार्ग पर कच्ची पगडंडी के किनारे माओवादियों द्वारा पूर्व में लगाया गया लगभग पांच किलोग्राम वजन का टिफिन बम बरामद किया। समय रहते विस्फोटक का पता चलने से एक बड़ी अनहोनी टल गई।जानकारी के अनुसार, मार्ग के किनारे संदिग्ध विस्फोटक होने की सूचना मिलने पर बम निरोधक दस्ते और थाना बेदरे के जवानों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान करीब पांच किलोग्राम वजनी टिफिन प्रेशर आइईडी बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में विस्फोटक को प्रेशर स्विच प्रणाली से लगाया जाना पाया गया।इसके बाद बम निरोधक दस्ते के विशेषज्ञों और थाना बेदरे के जवानों ने निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मौके पर ही विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से संभावित दुर्घटना और जनहानि का खतरा टल गया। सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में लगातार सतर्कता बरती जा रही है, ताकि माओवादी गतिविधियों और उनके द्वारा लगाए गए विस्फोटकों से आम नागरिकों एवं जवानों को सुरक्षित रखा जा सके।

कबरा हाथी ने 11 दिन में 4 लोगों को कुचला

सरगुजा/सूरजपुरछत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में कबरा हाथी ने 45 साल की महिला को कुचलकर मार डाला। महिला अपने पति और बेटे के साथ पड़ोसियों को हाथी की मौजूदगी की सूचना देने घर से निकली थी। इसी दौरान वह हाथी की चपेट में आ गई।टना सूरजपुर के प्रेमनगर वनपरिक्षेत्र की है। महिला की जान लेने के बाद हाथी देर रात सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक मुख्यालय के पास जंगल में पहुंच गया।हाथी की मौजूदगी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्वामी आत्मानंद स्कूल समेत कई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। वन विभाग की टीम हाथी की निगरानी कर रही है।कबरा हाथी पिछले 6 महीने में 18 लोगों की जान ले चुका है। उसे ट्रैंक्विलाइज कर रेडियो कॉलर लगाने की अनुमति पीसीसीएफ (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़ ने दे दी है।बता दें कि इससे पहले 8 नवंबर को कबरा हाथी ने दिवाली कार्यक्रम में जा रहे एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला था। वहीं, 1 नवंबर को सरगुजा-सूरजपुर सीमा पर भी हाथी ने दो लोगों की जान ले ली थी।

छठ पूजा के लिए भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा बना रहे हैं

छठ महापर्व के लिए सूर्य की प्रतिमा,रामानुजगंज के घाट में स्थापित की जाएगी मूर्ति, बंगाली मूर्तिकारों ने की कड़ी मेहनत

एक सत बुलेटिन ➤ बलरामपुर-रामानुजगंज

रामानुजगंज के नजदीक केरवाशीला गांव में छठ महापर्व से पहले बंगाली मूर्तिकार भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं। रामानुजगंज में छठ महापर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी है। शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बंगाली मूर्तिकार भगवान सूर्य की प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं। ऑर्डर के अनुसार मूर्तिकार मूर्तियां बनाने के काम में जुटे हुए हैं।महिला मूर्तिकार रंजीता सरकार ने बताया कि छठ पूजा के लिए भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा बना रहे हैं। इस बार सूर्य भगवान की पांच मूर्तियां बना रहे हैं। सूर्य देव के साथ उनका रथ और सात घोड़े भी रहेंगे। इनकी कीमत करीब आठ नौ हजार रूपए तक रखी गई है।



हम लोग सभी पूजा पाठ में मूर्तियां बनाते हैं। लेकिन रेट नहीं मिलने की वजह से ज्यादा लाभ नहीं हो पाता है। हमारा पूरा परिवार मिलकर ये काम करते हैं। आजीविका चलाते हैं बीते लगभग चालीस सालों से हम मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं - रंजीता सरकार, महिला मूर्तिकार

मेहनत और लागत के मुताबिक फायदा नहीं

इस संबंध में केरवाशीला गांव के रहने वाले मूर्तिकार दीपांकर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि छठ पूजा की तैयारियां चल रही हैं। मूर्तियों को बनाने में जितना खर्च पड़ता है, उस हिसाब से कम ही लाभ हमें मिल पा रहा है। इसमें सुतली, कांटी पुआल और बाहर से कलकत्ता की गंगा मिट्टी लाते हैं। इसके बाद रंग पेंट कपड़े ये सब लगता है। बहुत खर्चा होता है लेकिन उस हिसाब से फायदा नहीं हो पाता है।

छठ घाटों पर स्थापित होगी भगवान सूर्य देव की प्रतिमा

रामानुजगंज सहित ग्रामीण क्षेत्रों में छठ घाटों पर भगवान सूर्य देव की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजन आरती किए जाने की परंपरा है। जहां श्रद्धालु अपने आराध्य इष्ट देव के दर्शन पूजन करने के लिए उमड़ते हैं। इस दौरान छठ घाटों पर भक्ति और उत्सव का माहौल रहता है।

निखारने का अवसर प्रदान करेंगी

लारा में 21वीं सीनियर छत्तीसगढ़ राज्य अंतर जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ



एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

रायगढ़ जिले के लारा में छत्तीसगढ़ स्टेट वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित 21वीं सीनियर छत्तीसगढ़ राज्य अंतर जिला महिला एवं पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, अनुशासन और खेल भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री चौधरी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करें और अपने प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाएं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस तरह की प्रतियोगिताएं युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और अपनी खेल प्रतिभा निखारने का अवसर प्रदान करेंगी।

स्वरोजगार से लखपति दीदी बनीं ममता राजवाड़े

स्वरोजगार से लखपति दीदी बनीं ममता राजवाड़े

छोटी-छोटी बचत से शुरू हुआ आत्मनिर्भरता का सफर, समूह और ग्राम संगठन से मिले 2 लाख रुपये के ऋण से संवारी आर्थिक स्थिति

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन %बिहान % महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों को आजीविका गतिविधियों से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण महिलाएं न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं, बल्कि परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव भी रख रही हैं। सरगुजा जिले के आकांक्षी विकासखंड लखनपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कटकोना की श्रीमती ममता राजवाड़े भी ऐसी ही सशक्त महिला हैं, जिन्होंने छोटी-छोटी बचत से आत्मनिर्भरता की शुरुआत की और आज ईंट



निर्माण, बकरी पालन एवं खेती के माध्यम से लखपति दीदी के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

कभी छोटी जरूरतों के लिए भी नहीं होते थे पैसे, अब बनीं आत्मनिर्भर

श्रीमती ममता राजवाड़े बताती हैं कि बिहान योजना से जुड़ने से पहले उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य नहीं थी। घर की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसों की परेशानी होती थी। कई बार दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता था। ऐसे समय में महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ना उनके जीवन में बदलाव की शुरुआत बना।उन्होंने बताया कि समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने मात्र 10 रुपये की छोटी बचत से शुरुआत की। धीरे-धीरे समूह की गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी और उन्हें ऋण की सुविधा मिलने लगी। इस आर्थिक सहयोग से उन्होंने स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाया। आज वे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ आय बढ़ाने के लिए विभिन्न आजीविका गतिविधियां संचालित कर रही हैं।

सुरक्षाबलों को सर्च ऑपरेशन में मिली सफलता

बीजापुर में 5 किलो का आईईडी बरामद

एक सत बुलेटिन ➤ बीजापुर

बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। उसके बाद से लगातार बस्तर संभाग में सुरक्षाबल एंटी नक्सल ऑपरेशन और सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर पुलिस ने करकेली से बेदरे मार्ग पर सड़क किनारे कच्ची पगडंडी में माओवादियों द्वारा पूर्व में लगाया गया लगभग 5 किलोग्राम वजनी टिफिन प्रेशर ढ्ढश्वष्ठ बरामद किया है। इसे सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया गया है।

बेदरे से आईईडी बरामद

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बीडीएस (बम निरोधक दस्ता) एवं थाना बेदरे के जवानों ने क्षेत्र में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। इस दौरान यहां आईईडी का पता चला। जांच में सामने आया कि माओवादियों ने इसे प्रेशर स्विच सिस्टम के माध्यम से लगाया था। इसके बाद मौके पर पहुंची बीडीएस की टीम ने निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए डीमाइनिंग की कार्रवाई की। उसके बाद सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया।बीडीएस एवं थाना बेदरे की संयुक्त टीम द्वारा सतर्कता के साथ कार्रवाई करते हुए बम को बरामद किया गया।

रायपुर समेत इन जिलों में बदला मौसम का मिजाज; पड़ने लगी ठंड, लोगों ने निकाले गर्म कपड़े

न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर फिलहाल थम गया है

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

आगामी पांच दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ स्थानों पर तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल ठंड की रफ्तार बढ़ने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में आने वाली हवाओं की दिशा में बदलाव देखा जा रहा है। इस वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर फिलहाल थम गया है।

छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पहले गुलाबी ठंड के बाद अब पूरी तरह से ठंड पड़ने लगी है। सुबह और शाम के समय ठंड लग रही है। राजधानी रायपुर में शाम पांच बजे से सुबह नौ बजे तक ठंड देखी जा रही है। बाकी

पिछले 24 घंटे में कैसा रहा मौसम

दिवाली से पहले से ही प्रदेश में रात के तापमान में लगातार गिरावट का दौर शुरू हो गया था। इसके चलते रात और सुबह के समय ठंड का एहसास बढ़ने लगा था, लेकिन अब तापमान में गिरावट की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। पिछले 24 घंटे के दौरान अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।11 नवंबर को रायपुर में मौसम साफ रहा। कहीं-कहीं बादल तो कहीं हल्की धूप खिली रही।

अन्य जिलों में भी ठंड शुरू हो गई है। बस्तर और सरगुजा संभाग के पहाड़ी इलाके वाले जिलों में ठंड बढ़ती जा रही है। इस वजह से लोग गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिये हैं।आगामी पांच दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ स्थानों पर तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल ठंड की रफ्तार बढ़ने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में आने वाली हवाओं की दिशा में बदलाव देखा जा रहा है। इस वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर फिलहाल थम गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ठआने वाली ठंडी हवाएं हैं।

कलेक्टर कार्यालय से शासन को भेजी गई कार्रवाई की रिपोर्ट

पटवारियों पर ब्रेक इन सर्विस और निलंबन की कार्रवाई, धान खरीदी शुरू होने से पहले सरकार का बड़ा एक्शन

एक सत बुलेटिन ➤ सुकमा

13 अक्टूबर से कामकाज से दूर रहकर आंदोलन कर रहे पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोरिया जिले में हड़ताल में शामिल 50 पटवारियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं बस्तर में 99 तो सुकमा में 56 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन रोक दिया गया है।कोरिया में 50 हड़ताली पटवारियों के विरुद्ध 'ब्रेक इन सर्विस' अर्थात सेवा-विच्छेद के आदेश जारी किए गए हैं। दो को निलंबित किया गया है। प्रशासन ने पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन भी रोक दिया है।कलेक्टर कार्यालय द्वारा 11 नवंबर को सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को भेजे गए पत्र में हड़ताल और उसके विरुद्ध की गई



कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। पत्र के अनुसार निलंबित किए गए दोनों पटवारियों के विरुद्ध विभागीय जांच करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। हड़ताल में शामिल सभी 50 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

जिले के 59 में से 50 पटवारी हड़ताल पर

कोरिया जिले में कुल 59 पटवारियों के पदस्थ होने की जानकारी दी गई है। इनमें से 50 पटवारी 13 अक्टूबर से जारी हड़ताल में शामिल हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले की चार तहसीलों में हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बैकुंठपुर तहसील में कुल 19 पटवारियों में से 17 हड़ताल पर हैं। इसी तरह पटना तहसील में 17 में से 15, पोड़ी-बचरा तहसील में 11 में से नौ और सोनहत तहसील में 12 में से नौ पटवारी आंदोलन में शामिल हैं। इस तरह जिले में पदस्थ कुल पटवारियों में से अधिकांश के हड़ताल पर रहने से राजस्व विभाग का मैदानी कामकाज प्रभावित होने की स्थिति बनी हुई है।

पटना और सोनहत तहसील के एक-एक पटवारी निलंबित

प्रशासनिक कार्रवाई के तहत निलंबित किए गए दो पटवारियों में एक पटना तहसील और दूसरा सोनहत तहसील का बताया गया है। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा सभी 50 हड़ताली पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है। प्रशासन की ओर से जारी ब्रेक इन सर्विस के आदेश और वेतन रोकने की कार्रवाई को हड़ताल के खिलाफ अब तक की बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई माना जा रहा है।

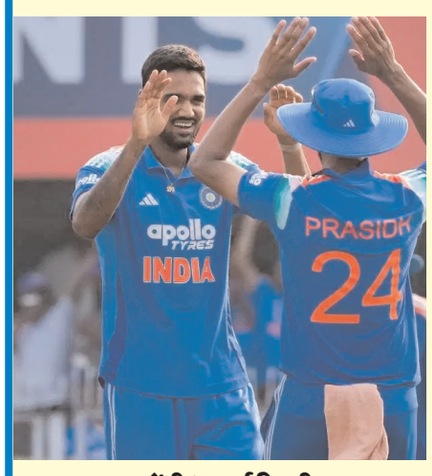
9 पटवारी हड़ताल से रहे अलग

एक ओर जहां जिले के 50 पटवारी हड़ताल में शामिल हैं, वहीं नौ पटवारियों ने आंदोलन से दूरी बनाए रखी है। इनमें आठ परिवीक्षाधीन पटवारी और एक नियमित पटवारी शामिल हैं। इन कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल नहीं होने से जिले में कुछ स्तर पर राजस्व संबंधी कार्यों के संचालन की गुंजाइश बनी हुई है।

बस्तर में 99 पटवारियों पर ब्रेक इन सर्विस, 17 निलंबित

बस्तर में भी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे पटवारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब तक की बड़ी कार्रवाई की है। करीब एक महीने से जारी हड़ताल के बीच प्रशासन ने 99 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस घोषित कर दिया है जबकि 17 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है।दरअसल पटवारी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते राजस्व विभाग से जुड़े कई काम प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से हड़ताल पर गए सभी 136 पटवारियों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

वनडे सीरीज से एक और भारतीय खिलाड़ी होगा बाहर!



एजेंसी ➤ नई दिल्ली

न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज के बीच टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों ने वनडे टीम का साथ छोड़ा है। इसमें कप्तान शुभमन गिल, विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल और तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज का नाम शामिल है। इस लिस्ट में अब एक और नाम शामिल होने जा रहा है, हालांकि ये खिलाड़ी टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वॉड का हिस्सा नहीं है।एक और भारतीय खिलाड़ी छोड़ेगा वनडे टीम का साथ

न्यूजीलैंड दौरे पर अपनी घातक गेंदबाजी से तहलका मचा रहे भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ पांच मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले से बाहर रह सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय टीम मैनेजमेंट इस लंबे कद के तेज गेंदबाज को वनडे स्क्वॉड से रिलीज कर सीधे वेलिंगटन में भारतीय टेस्ट टीम के कैंप से जोड़ने की योजना बना रहा है।रिपोर्ट के मुताबिक, माउंट माउंगानुई में शुक्रवार को होने वाले चौथे वनडे मुकाबले के खत्म होने के बाद गुरनूर बराड़ को रिलीज करने पर आखिरी मुहर लगाई जाएगी। भारतीय टीम मैनेजमेंट की इस रणनीति के पीछे न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजी की काट ढूंढना अहम उद्देश्य है। न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम में लंबे कद के कई खतरनाक तेज गेंदबाज शामिल हैं, जो उछाल भरी पिचों पर भारतीय बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। ऐसे में बराड़ वेलिंगटन में टेस्ट स्क्वॉड के साथ जुड़कर नेट्स में भारतीय बल्लेबाजों को कीवी गेंदबाजों जैसी ऊंचाई और उछाल के खिलाफ प्रैक्टिस करने में मदद करेंगे।गुरनूर बराड़ मौजूदा वनडे सीरीज में भारत के सबसे सफल गेंदबाज बने हुए हैं। उन्होंने सीरीज की 2 पारियों में सिर्फ 10।57 के औसत से 7 विकेट चटकाए हैं और फिलहाल सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इसी साल जून में धर्मशाला में अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू करने वाले बराड़ ने काफी कम समय में खुद को साबित किया है।

हॉर्स रेसिंग में बड़ा हादसा,



स्ट्रेलियाई हॉर्स रेसिंग जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। 22 साल की जॉकी इजी नील का न्यू साउथ वेल्स में रेस के दौरान हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद निधन हो गया। 8 नवंबर को आयोजित 'वॉरेन शायर कॉटन कप' प्रतियोगिता के दौरान वो अपने घोड़े मारनू से अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई थीं। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां लाइफ सपोर्ट पर रहने के बाद मंगलवार, 10 नवंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया।

26 मिनट तक हवा में अटकी टीम इंडिया के खिलाड़ियों की सांसे,



एजेंसी ➤ नई दिल्ली

वेलिंगटन में टीम इंडिया के प्लेन को लैंड कराने की पहली कोशिश नाकाम रही। प्लेन रनवे के करीब तो आई मगर तेज हवाओं ने पायलट को फिर से उसे ऊपर ले जाने को मजबूर कर दिया।न्यूजीलैंड में तीसरे वनडे के बाद टीम इंडिया दो धड़ों में बंट गई। एक वो जो जिसने टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए वेलिंगटन कूच किया और दूसरी वो जिसने वनडे सीरीज के आखिरी दो मुकाबले खेलने के लिए माउंट माऊंगनुई का रूख किया। अब जो टीम आखिरी 2 वनडे खेलने माउंट माऊंगनुई पहुंची, उनका सफर तो शानदार रहा। उनका वहां के पारंपरिक हका डांस के साथ स्वागत भी किया गया।

ऋतुराज गायकवाड़ ने अबतक 12 वनडे मैचों में 36।55 की औसत से 329 रन बनाए हैं

रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन नहीं करेंगे ओपनिंग, शुभमन गिल की जगह लेगा ये खिलाड़ी

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

टीम में वैसे ईशान किशन भी हैं जो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपनिंग की जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंपी जाएगी।

ऋतुराज गायकवाड़ का ओपनिंग करने का मतलब ये है कि ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने वाले हैं। बता दें चौथे और पांचवें वनडे मैच में शुभमन गिल, केएल राहुल नहीं खेलेंगे वो दो मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए वनडे टीम से रिलीज कर दिए गए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ का ओपनिंग करने का मतलब ये है कि ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने वाले हैं। बता दें चौथे और पांचवें वनडे मैच में शुभमन गिल, केएल राहुल नहीं खेलेंगे वो दो मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए वनडे टीम से रिलीज कर दिए गए हैं।



ऋतुराज गायकवाड़ के लिए ओपनिंग करना आसान नहीं होगा। न्यूजीलैंड की मुश्किल परिस्थितियों में ओपनर्स के लिए टिकना मुश्किल रहा है। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने हालांकि अबतक वनडे में अच्छा प्रदर्शन किया है।

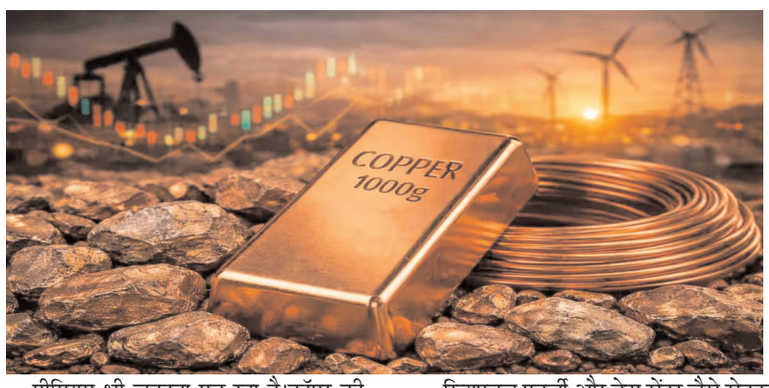
ऋतुराज गायकवाड़ के लिए ओपनिंग करना आसान नहीं होगा। न्यूजीलैंड की मुश्किल परिस्थितियों में ओपनर्स के लिए टिकना मुश्किल रहा है। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने हालांकि अबतक वनडे में अच्छा प्रदर्शन किया है। ऋतुराज गायकवाड़ ने अबतक 12 वनडे मैचों में 36।55 की औसत से 329 रन बनाए हैं। गायकवाड़ ने 1 वनडे शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। हालांकि उनके बल्ले से ये शतक मिडिल ऑर्डर में निकला था और अब उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालनी है।ऋतुराज गायकवाड़ ने अबतक 12 वनडे मैचों में 36।55 की औसत से 329 रन बनाए हैं।

व्यापार

दुनिया तांबे के पीछे, ज्यादा पैसे देने को तैयार!

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

भारत में कॉपर की कीमत अगस्त में करीब ?1,400 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। ग्लोबल स्तर पर बढ़ती मांग और सीमित सप्लाई के बीच कॉपर बाजार में दबाव बढ़ रहा है। पावर ग्रिड, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी और ढ्ढ डेटा सेंटर जैसे सेक्टर इसकी खपत बढ़ा रहे हैं।भारत में तांबे की कीमत अगस्त 2026 में करीब ?1,400 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। 17 अगस्त को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि। (ख्रष्ठङ्क) पर कॉपर कॉन्ट्रैक्ट भी लगभग इसी स्तर पर कारोबार कर रहे थे। बाजार में सिर्फ कीमत ही नहीं बढ़ी है, बल्कि तुरंत सप्लाई हासिल करने के लिए खरीदारों को



प्रीमियम भी चुकाना पड़ रहा है।कॉपर की कीमतों में तेजी के पीछे ग्लोबल डिमांड और सप्लाई के बीच बढ़ता अंतर बड़ी वजह माना जा रहा है। पावर ग्रिड, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी और डेटा सेंटर जैसे सेक्टर में कॉपर की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से लंदन मेटल एक्सचेंज के करीब बनी हुई हैं।

एयरटेल पेमेंट्स बैंक की नई चेयरपर्सन होंगी शबनम सिन्हा·

सुनील मित्तल 10 साल बाद पद छोड़ेंगे, 30 सितंबर को कंपनी के बोर्ड से हटेंगे

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

वर्ल्ड बैंक की पूर्व लीड स्पेशलिस्ट और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डॉ. शबनम सिन्हा 1 अक्टूबर 2026 से बैंक की नई चेयरपर्सन के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगी।

एयरटेल पेमेंट्स बैंक की नई चेयरपर्सन शबनम सिन्हा होंगी। वे 1 अक्टूबर 2026 से यह पद संभालेंगी। शबनम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील भारती मित्तल की जगह लेंगी। मित्तल 30 सितंबर को अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा करके बोर्ड से हट जाएंगे।डॉ. शबनम सिन्हा के पास बैंकिंग, गवर्नेंस और डिजिटल बदलाव का 30 से ज्यादा सालों का ग्लोबल अनुभव है। उन्होंने 2010-2025 यानी 15 साल वर्ल्ड बैंक में बतौर लीड स्पेशलिस्ट काम किया। यहां उन्होंने एशिया, यूरोप और अफ्रीका में 4 बिलियन डॉलर यानी करीब ?38,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी संभाली।

वर्ल्ड बैंक से पहले वह ढ्ढरू स्रस्र एजुकेशन की



ष्ठश्वह्र रह चुकी हैं और ह्लढ्ढष्ठ व ह्लष्ठश्वत्रक्क के साथ भी लंबे समय तक काम कर चुकी हैं। फिलहाल वह एयरटेल पेमेंट्स बैंक, वेदांता और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे बड़े संस्थानों के बोर्ड में शामिल हैं।शबनम सिन्हा बोली- जिम्मेदारी मिलना सम्मान की बात

डॉ. शबनम ने कहा कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक की कमान संभालना मेरे लिए गर्व की बात है, खासकर ऐसे वक्त में जब डिजिटल बैंकिंग देश की तरक्की में सबसे अहम रोल निभा रही है। बैंक ने आसान तकनीक के जरिए एक ऐसा मजबूत और भरोसेमंद जरिया तैयार किया है,।

राज्यों का आरोप है कि मेटा को पता था।

मेटा पर भारी जुर्माने का संकट

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

मेटा अब एक नए कोर्ट केस का सामना करने जा रही है, जहां जहां उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं. प्लेटफॉर्म पर आरोप हैं कि उसकी वजह से लोगों को सोशल मीडिया की लत लग रही है और उसके ऐप्स कई तरह के नुकसान पहुंचा जा रहे हैं।

साथ ही उसके ऐप्स की वजह से बच्चों की मेंटल हेल्थ भी प्रभावित हो रही है, जिसके कारण कंपनी को दर्जनों केस का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कंपनी को 1।4 ट्रिलियन डॉलर (करीब 133।92 लाख करोड़ रुपये) के जुर्माने तक भरना पड़ सकता है।

नए मामले की सुनवाई मंगलवार को कैलिफोर्निया के ओकलैंड स्थित संघीय अदालत में शुरू की जाएगी। बीते सप्ताह मेटा ने इस मामले को खारिज कराने की मांग की थी, लेकिन कंपनी की अर्जी को कंपनी ने



स्वीकार नहीं किया।

सीईओ मार्क जकरबर्ग को पड़ेगा पेश

इस केस के दौरान मेटा के टॉप ऑफिसर्स और कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग तक की सुनवाई हो सकती है। साथ ही कंपनी पर बहुत मोटा जुर्माना तक लगाया जा सकता है। राज्यों ने मेटा पर आरोप लगाया था कि मेटा ने जानबूझकर ऐसे फीचर्स को तैयार किया है, जो असल में यूजर्स को उसके प्लेटफॉर्म का आदि बनाते हैं।

2023 में मेटा के खिलाफ दायर केस से कनेक्ट हैं

यह मामला साल 2023 में कई अमेरिकी राज्यों की ओर से मेटा के खिलाफ दायर किए गए केस से कनेक्टेड है। यह कार्रवाई कंपनी की सुरक्षा नीतियों को लेकर कई राज्यों की जांच के बाद हुई, जिसके बाद जांच में बच्चों और किशोरों को होने वाले गंभीर नुकसान सामने आए थे। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दी है।

मेटा के खिलाफ आरोप सुनेंगें

सुनवाई के दौरान जज यवोन गोंजालेज रोजर्स कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी के आरोपों को सुनेंगे, जिसमें मेटा पर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि मेटा ने अपने ऐप्स की सुरक्षा को लेकर जानबूझकर गुमराह किया और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का उल्लंघन किया।

चार राज्यों समेत कुल 29 राज्य मेटा पर चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट के उल्लंघन के आरोप लग चुके हैं। राज्यों का आरोप है कि मेटा को पता था।

विदेश में मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की बंपर डिमांड



विदेश में मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की बंपर डिमांड

मारुति सुजुकी भारत में सबसे ज्यादा कारें बेचती है. मारुति सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि विदेशों में एक्सपोर्ट के लिए भी कई कारें बनाती है। ऐसी ही एक कार मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स है, जो काफी ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। इस कार की 2 लाख यूनिट्स को भारत से बाहर एक्सपोर्ट किया जा चुका है। इस आंकड़े तक यानी 2 लाख एक्सपोर्ट तक मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स सबसे तेजी से पहुंची है। कॉम्पैक्ट एसयूवी को यहां तक पहुंचने में 38 महीनों का वक्त लगा है। फ्रॉन्क्स का एक्सपोर्ट जून 2023 में शुरू हुआ। फिलहाल इस मेड इन इंडिया एसयूवी को 90 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। मारुति इस कार की मैन्युफैक्चरिंग गुजरात के हंसलपुर प्लांट में करती है।



शिवराज की किसानों के लिए बड़ी पहल

दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 'भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस-2026' का बुधवार को भारत मंडपम में आगाज हुआ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और इंडिया की वाइस-चेयरपर्सन एंड एग्जीक्यूटिव एडिटर-इन-चीफ कली पुरी की मौजूदगी में दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस वर्ष सम्मेलन की थीम 'स्मार्ट किसान, विकसित भारत' है, जिसके तहत पहले दिन राजनेताओं, कृषि विशेषज्ञों और उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने खेती की चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा की। सम्मेलन के दूसरे दिन गुरुवार रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है।भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भारतीय कृषि को नई ऊंचाइयों तक ले जाने, किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए ऐसा मंच बेहद महत्वपूर्ण है, जहां देश के अलग-अलग हिस्सों से आए किसान, कृषि विशेषज्ञ और उद्योग जगत के लोग एक साथ बैठकर खेती-किसानी को आगे बढ़ाने के रास्तों पर चर्चा कर सकें। उन्होंने इस आयोजन के लिए इंडिया का आभार जताते हुए कहा कि दो दिनों तक होने वाला यह संवाद कृषि क्षेत्र के लिए दूरगामी और सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की रीढ़ हमारे अन्नदाता और किसान हैं, देश की बड़ी आबादी होने के बावजूद भारत को वैश्विक खाद्य संकट जैसी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा है, तो इसका बड़ा श्रेय किसानों को जाता है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब देश में अनाज की कमी हुआ करती थी, लेकिन किसानों ने दिन-रात मेहनत करके भारत को उस स्थिति से बाहर निकाला। आज देश न केवल अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, बल्कि दूसरे देशों की खाद्य सुरक्षा में भी योगदान दे सकता है।

विचार

जनजाति विकास के लिए शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों से हो रहा है संवर्धन

मोहन दास

लेकख

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान पीएम-जनमन महासमुंद जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति कमार समुदाय के लिए उम्मीद, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया माध्यम बन रहा है। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। केंद्र और राज्य शासन के समन्वित प्रयासों से कमार बस्तियों में विकास और वर्षों सजीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

कभी जंगलों और दुर्गम रास्तों के बीच बसे छोटे-छोटे डेरों में अभावों के बीच जीवन बिताने वाला कमार जनजाति का समुदाय आज विकास की मुख्यधारा से जुड़कर नई राह पर आगे बढ़ रहा है। जिन बस्तियों तक पहुंचना कभी मुश्किल था, वहां अब पक्की सड़कें पहुंच रही हैं। जिन घरों में अंधेरा और असुरक्षा थी, वहां बिजली की रोशनी और पक्के मकानों ने जगह ले ली है। स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने से इन परिवारों के जीवन में व्यापक बदलाव दिखाई देने लगा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान पीएम-जनमन महासमुंद जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति कमार समुदाय के लिए उम्मीद, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया माध्यम बन रहा है। वहीं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में शासन द्वारा इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि कमार समुदाय के प्रत्येक परिवार तक बुनियादी सुविधाएं और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। केंद्र और राज्य शासन के समन्वित प्रयासों से कमार बस्तियों में विकास और वर्षों से सुविधाओं से वंचित परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

आदिम जाति अनुसंधान केंद्र के आधारभूत सर्वेक्षण 2015-16 के आधार पर महासमुंद जिले में इनका सर्वे कार्य किया गया था जिसके आधार पर वर्तमान में कुल 923 कमार परिवार में कुल जनसंख्या 3309 है, जिनमे पुरुष जनसंख्या 1614 एवं महिला जनसंख्या 1695 है। सर्वे के अनुसार महासमुंद विकासखंड में



41 ग्राम, बागबाहरा विकासखंड में 33 ग्राम एवं पिथौरा विकासखंड में 2 ग्राम कुल 76 ग्राम में कमार परिवार निवासरत है।

जिला प्रशासन द्वारा इस योजना को गंभीरता से लागू करते हुए कमार जनजाति के हर परिवार तक पहुंचने का प्रयास किया गया। जिससे जिले के 26 सड़क विहीन बसाहटों में पक्की सड़कों का निर्माण किया गया है। इससे दूर-दराज के डेरों का संपर्क मुख्य गांवों और शहरों से जुड़ने लगा। नल-जल योजना के माध्यम से सभी घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। जिन घरों में कभी अंधेरा रहता था, वहां अब बिजली पहुंच चुकी है, अब बच्चे रात में भी पढ़ाई कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 678 कच्चे घरों की जगह पक्के मकानों का निर्माण हुआ, जिससे इन परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिला। बहुउद्देशीय केंद्रों की स्थापना से एक ही स्थान पर आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य सेवाएं और आजीविका से जुड़ी गतिविधियां शुरू हुईं, जिससे महिलाओं और बच्चों को विशेष लाभ मिला। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं अब सीधे इन बस्तियों तक पहुंच रही हैं, जिससे इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ता।

आधारभूत सुविधाओं के साथ लोगों को उनके अधिकारों से भी जोड़ा गया। विशेष शिविरों के माध्यम से शत प्रतिशत पात्र हितग्राहियों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाते और जाति प्रमाण पत्र बनवाए गए। किसान सम्मान निधि हेतु का लक्ष्य शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। अब हर परिवार को नियमित रूप से राशन मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा योजनाओं की राशि सीधे उनके खातों में पहुंच रही है।

विचार

तप रही धरती

नेहा जैन

लेखक

पिछले तीन दशकों में जलवायु परिवर्तन पर कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं। वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के माध्यम से वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके बावजूद ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। इससे स्पष्ट है कि केवल समझौते और घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं। अब जरूरत ऐसे फैसलों की है, जिनकी समयबद्ध समीक्षा हो और जिनके परिणाम भी दिखाई दें। इसी उद्देश्य से कॉप-31 को क्रियान्वयन का सम्मेलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। देशों को अपने जलवायु लक्ष्यों की प्रगति का हिसाब देना होगा और उत्सर्जन कम करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनानी होगी।जलवायु संकट की सबसे बड़ी वजह कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग है। इनसे निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसें धरती का तापमान बढ़ा रही हैं। वर्ष 2023 में दुबई



में हुए कॉप-28 में पहली बार ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की बात स्वीकार की गई थी। हालांकि, इस बदलाव की स्पष्ट समयसीमा और कार्ययोजना अभी भी बड़ी चुनौती है। इसके लिए सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार, बैटरी भंडारण, आधुनिक बिजली ग्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना जरूरी है। उद्योगों में ऊर्जा की खपत कम करने वाली तकनीकों को अपनाना भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ऊर्जा परिवर्तन केवल बिजली उत्पादन का तरीका बदलने तक सीमित नहीं होना चाहिए। कोयला और अन्य पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के रोजगार और आजीविका की सुरक्षा भी जरूरी है। स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव ऐसा होना चाहिए, जिससे गरीबों और श्रमिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। इसी को न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन कहा जाता है।जलवायु संकट का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जिन विकसित देशों का ऐतिहासिक उत्सर्जन अधिक रहा है, उनके पास इससे निपटने के लिए अधिक संसाधन हैं। दूसरी ओर, विकासशील और छोटे द्वीपीय देश जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक नुकसान झेल रहे हैं। इन देशों को स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के साथ बाढ़ नियंत्रण, सूखा प्रबंधन, जल संरक्षण, तटीय सुरक्षा और जलवायु अनुकूल खेती के लिए भी धन की जरूरत है। इसके अलावा जलवायु आपदाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और हुए नुकसान की भरपाई के लिए हानि एवं क्षति (लॉस एंड डैमेज) की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है।

विकसित देशों को विकासशील देशों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता और आधुनिक तकनीक उपलब्ध करानी चाहिए। यह सहायता केवल कर्ज के रूप में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले से आर्थिक दबाव झेल रहे देशों पर भारी ब्याज वाले ऋणों का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। जलवायु न्याय का तकाजा है कि संकट का सबसे अधिक भार उन लोगों पर न पड़े, जिनका उत्सर्जन में योगदान सबसे कम रहा है।

कॉप-31 में 11 नवंबर को शून्य अपशिष्ट (जीरो वेस्ट) का विषय प्रमुखता से सामने आया। कचरे का सही प्रबंधन भी जलवायु परिवर्तन से निपटने का महत्वपूर्ण उपाय है। लैंडफिल में जमा जैविक कचरे से मीथेन गैस निकलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। इसलिए कचरे को अलग-अलग करना, पुनर्चक्रण, खाद बनाना, वस्तुओं का दोबारा उपयोग और खाद्य अपशिष्ट में कमी लाना जरूरी है।इसी दिन अंताल्या में विश्व नेताओं की दो दिवसीय शिखर बैठक भी शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने अपने संबोधन में जीवाश्म ईंधन को डायनासोर की तरह इतिहास का हिस्सा बनाने की बात कही। उन्होंने जलवायु कार्रवाई की धीमी गति पर आह्वान किया।

(एक नजर)

6 महीने के लिए बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट

उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट 11 नवंबर 2026 को भाई दूज पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ मंदिर के कपाट बंद किए गए। इसके साथ ही इस साल की केदारनाथ यात्रा का समापन हो गया है। अब अगले करीब छह महीने तक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन उनके मुख्य धाम में नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए अगले साल तक इंतजार करना होगा। सर्दियों में भी बाबा केदार की पूजा-अर्चना जारी रहेगी। ऐसे में सवाल है कि आखिर अगले छह महीने तक बाबा केदार कहां विराजेंगे और भक्त उनके दर्शन कहां कर सकेंगे? तो आइए जानते हैं।धार्मिक मान्यता के अनुसार, सर्दियों में भारी बर्फबारी और ठंड के कारण केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद बाबा केदार की चल विग्रह डोली को उनके शीतकालीन निवास ऊखीमठ ले जाया जाता है।

विचार

उद्योगों को कैसे लुभाएंगे शुभेंदु

- अशोक भाटिया

लेखक

पश्चिम बंगाल सरकार की नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय लाभों का विस्तृत पैकेज दिया गया है। इसमें औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन शुरू होने के बाद खर्च की भरपाई, सब्सिडी और कई अन्य लाभ देने का वादा किया गया है।लेकिन प्रशासन ने निवेशकों को मिलने वाले फायदों का ब्योरा तो विस्तार से दिया है पर एक बुनियादी सवाल पर स्थिति साफ नहीं की है। आखिर इन उद्योगों के लिए जमीन कहां से आएगी?पश्चिम बंगाल निवेश प्रोत्साहन नीति, 2026 में विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए व्यापक प्रोत्साहन व्यवस्था की गई है। लेकिन नीति में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरकार औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित करेगी। खासकर उन बड़ी परियोजनाओं के लिए जिनके लिए एक ही जगह पर बड़े भूखंडों की जरूरत होगी।

यह कमी इसलिए अहम है क्योंकि बंगाल में औद्योगीकरण की राह में जमीन की उपलब्धता लंबे समय से बड़ी



बाधा रही है। सिंगूर और नंदीग्राम में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार की जमीन अधिग्रहण मुहिम के राजनीतिक नतीजे आज भी राज्य की औद्योगिक विकास नीति को प्रभावित करते हैं। इसके बाद सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस सरकार ने बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण से दूरी बनाए रखी। उसने निजी निवेशकों को जमीन मालिकों से सीधे बातचीत करने के लिए छोड़ दिया।शासन में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संकेत दिया है कि उनकी सरकार इन दोनों तरीकों से अलग रास्ता अपनाना चाहती है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की कि सरकार किसानों से सीधे जमीन खरीदकर और लैंड पूलिंग व्यवस्था के जरिए उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी।अधिकारी ने कहा, ÷हम हाथ पर हाथ धरे बैठकर उद्योगपतियों से यह नहीं कहेंगे कि वे अपनी इकाइयों के लिए खुद जमीन खरीदें। न ही हम किसानों से बंदूक की नोक पर जमीन अधिग्रहित करेंगे। हम किसानों से सीधे जमीन खरीदकर और लैंड पूलिंग व्यवस्था के जरिए लैंड बैंक बनाएंगे।प्रस्तावित लैंड पूलिंग व्यवस्था के तहत जमीन मालिक स्वेच्छा से अपने भूखंड सरकार को देंगे। सरकार उस जमीन का विकास करेगी और उसका एक हिस्सा मूल मालिकों को लौटा देगी। अधिकारी ने कहा कि सरकार विकसित जमीन का 25-30 प्रतिशत हिस्सा जमीन मालिकों को वापस देगी। इसके अलावा, उनकी जमीन पर स्थापित होने वाले उद्योगों में उन्हें एक निश्चित प्रतिशत हिस्सेदारी भी दी जाएगी।मुख्यमंत्री ने कहा, ÷हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की नीतियों के अनुरूप जमीन विकसित करने के बाद उसका 25-30 प्रतिशत हिस्सा जमीन मालिकों को लौटा देंगे। इसके अलावा हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जमीन देने वाले लोगों को उस पर विकसित होने वाले उद्योगों में एक निश्चित प्रतिशत हिस्सेदारी मिले।हालांकि इन आश्वासनों को अभी तक औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में विस्तार से शामिल नहीं किया गया है। दस्तावेज में नक्शे के आधार पर औद्योगिक जमीन की सूची तैयार करने का जिक्र है। इसमें प्रकाशित मानदंडों और ऑनलाइन आवेदन के जरिए जमीन आवंटित करने का प्रावधान भी है। साथ ही पहले से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों और अधिसूचित औद्योगिक गलियारों के किनारे स्थित औद्योगिक पार्कों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।लेकिन नीति में यह नहीं बताया गया है कि फिलहाल सरकार के पास कितनी जमीन उपलब्ध है, वह कितनी अतिरिक्त जमीन जुटाना चाहती है या सैकड़ों एकड़ जमीन की जरूरत वाली परियोजनाओं के लिए एक साथ बड़े भूखंड कैसे उपलब्ध कराएगी। प्रस्तावित लैंड बैंक को कब तक चालू किया जाएगा, इसकी समयसीमा भी नहीं दी गई है।यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार जिन क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहती है उनमें से कई को बड़े भूखंडों की जरूरत होती है। नीति में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी, रक्षा, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल विनिर्माण और महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें से कई उद्योगों के लिए बड़े पैमाने पर जमीन, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे और बिजली-पानी जैसी सुविधाओं की निर्बाध उपलब्धता जरूरी होती है।अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जमीन जुटाने के सरकार के दोहरे तरीके का विस्तृत ब्योरा एक व्यापक भूमि नीति में शामिल किया जाएगा। इसे अलग से जारी किए जाने की उम्मीद है। वरिष्ठ नौकरशाहों ने यह भी स्वीकार किया है।



पेंटिंग के शौक से मिलेगा रोजगार

अगर आप पेंटिंग का शौक रखते हैं और आप को रंगों से खेलना अच्छा लगता है तो आप एक पेंटिंग को अपना पेश बना सकते हैं। अगर आप में कलात्मकता है तो आप इस क्षेत्र में बेहतरीन कॅरियर बना सकते हैं। आज एक पेंटर आर्ट गैलरीज से लेकर अखबर , मैगजीन, पोस्टर, फिल्म व टीवी इंडस्टी में काम कर सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हैं या फिर किसी फाइन आर्ट इंस्टीटयूट व कॉलेज में बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। अगर चाहें तो खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं।

बचपन में हम सभी ने अपने हाथों में ब्रश उठाकर पेंटिंग की है। पेंटिंग करना यकीनन हर किसी के मन को सुकून देता है, लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, वह शौक कहीं पीछे छूटने लगता है। काम की आपाधापी में ब्रश हाथों से कब दूर चला जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आपको पेंटिंग करना बेहद पसंद है तो क्यों न अपने इसी शौक को आप अपना कॅरियर बना लें। तो चलिए जानते हैं इस क्षेत्र के बारे में-

संभावनाएं

पेंटिंग एक बेहतरीन कॅरियर है और एक पेंटर आर्ट गैलरीज से लेकर न्यूजपेपर, मैगजीन, पोस्टर, फिल्म व टीवी इंडस्टी में आर्टवर्क की तलाश कर सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हैं या फिर किसी फाइन आर्ट इंस्टीटयूट व कॉलेज में बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। अगर चाहें तो खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलें।

आमदनी

इस क्षेत्र में आमदनी इस बात पर निर्भर करती है कि आपका काम लोगों को कितना पसंद आता है, लेकिन फिर भी शुरूआती दौर में आप बीस से पच्चीस हजार आसानी से कमा सकते हैं। वहीं कुछ सालों के अनुभव व

क्या होता है काम

एक पेंटर कई तरह के काम करता है। उसका काम घर से लेकर बाहर तक हो सकता है। वह सिर्फ छोटे स्केल पर कागज पर पेंटिंग नहीं करता और न की उसका काम सिर्फ कैनवास तक सीमित है, बल्कि वह घर को नया रुप देने के साथ ही किसी या अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी अपना कलात्मकता दिखा समा है।

स्किल्स

इस क्षेत्र में सफलता के लिए सबसे जरूरी है आपका कल्पनाशील होना। इसके अलावा आपको पेंट कलर्स, टोन्स, हाइलाइट व आर्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आपको कलर्स के शेड्स व उनकी मिक्सिंग की जानकारी भी होनी चाहिए। कई बार एक पेंटर को कई बड़े प्रोजेक्ट करने होते हैं, इसलिए उसे टीम के साथ भी काम करना होता है। साथ ही आपको कई घंटों तक काम करना पड़ सकता है, इसके लिए आप फिजिकली व मेंटली तैयार रहें। एक पेंटर सिर्फ पेंटिंग ही नहीं करता, बल्कि अपने काम को लोगों के सामने पेश भी करता है, इसलिए आपके कम्युनिकेशन व लैंग्वेज स्किल भी अच्छी होनी जरूरी है।

एक पेंटर बनने के लिए अलग से किसी स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन पेंटिंग की बारीकियों को समझने और अपना हाथ साफ करने के लिए आप इस क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स जैसे बीए इन पेंटिंग, बीए पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्टस, बीएफए पेंटिंग, कोर्स आदि कर सकते हैं। इसके

पैराग्लाइडिंग निर्देशक बन दें लोगों को सही प्रशिक्षण व मार्गदर्शन



आजकल साहसी खेलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों के मन में पैराग्लाइडिंग के प्रति अलग ही क्रेज देखा जा रहा है, जिसके कारण पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर होना बेहद जरूरी है। एक पैराग्लाइडिंग निर्देशक का मुख्य काम आम लोगों से लेकर टूरिस्ट को सही तरह से प्रशिक्षण व मार्गदर्शन प्रदान करना।

अधिकांशत- जब भी लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने कहीं पहाडी क्षेत्रों में जातें हैं तो वे कुछ अलग और रोमांचक करना चाहते हैं। ऐसे में उनके मन में सबसे पहले पैराग्लाइडिंग करने का ख्याल आता है। लोगों के मन में भले ही जमीन से कई फुट ऊपर उड़ने की चाहत हो, परंतु इसको बिना निर्देशक की मदद के नहीं किया जा सकता। ये प्रोफेशनल्स होते हैं, जो आम लोगों को भी कुछ ही देर में आसमान में उड़ने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। जिससे लोगों को कुछ रोमांचक करने की चाहत बढ़ जाती है। इसके लिए पैराग्लाइडिंग निर्देशक की आवश्यकता भी अधिक महसूस की जाने

क्या होता है काम: आजकल लोगों के मन में पैराग्लाइडिंग के प्रति अलग ही क्रेज देखा जा रहा है, जिसके कारण पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर होना बेहद जरूरी है। एक पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर का मुख्य काम आम लोगों से लेकर टूरिस्ट को सही तरह से टेनिंग व गाइडेंस प्रदान करते हैं। वह उन्हें छोटी से छोटी बारीक बातों की भी जानकारी देते हैं ताकि आम पैराग्लाइडर के साथ कोई अनहोनी घटना न हो। वह ग्राउंड लेवल से लेकर 100 फुट से 1000 फुट तक उंचाई में उड़ने का अभ्यास कराते हैं। कुछ नए पैराग्लाइडर काफी डरते हैं, ऐसे में उनके मन से डर निकालने का काम भी एक पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर का ही होता है।

परिक्षाओं का मौसम चल रहा है। बोर्ड परिक्षाएं भी करीब आ रही हैं। कोरोना महामारी के कारण इस साल छात्रों के स्कूल भी ऑनलाइन रहे हैं। ऐसे में उन्हें परिक्षाओं में बेहतर अंक के लिए और ज्यादा मेहनत करने के साथ ही योजना के अनुसार तैयारी करनी होगी।

इस प्रकार करें तैयारी

परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले आपको अपना टाइमटेबल बनाना चाहिए। ध्यान रखें कि आपका टाइम टेबल पूरी तरह से सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया हो। संभव हो तो ऐसे विषय को ज्यादा तरजीह दें जिन्हें आप कठिन मानते हैं।आप उन विषय को भी समय जरूर दें जो आपके लिए आसान है। ऐसा करने से आप तय समय के

बीच-बीच में आराम करें

तैयारी करते समय समय-समय पर ब्रेक लेना जरूरी है. पढ़ाई के बीच में लिया जाने वाला यह ब्रेक आपको पहले पढ़ी गई चीजों को दोबारा से दोहराने का मौका देता है. इसके साथ ही यह ब्रेक

आपके मेमोरी को बेहतर करने में भी मददगार होता है. आम तौर पर छात्रों को अपनी पढ़ाई के बीच 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेते रहना चाहिए.

कठिन विषय को ज्यादा समय दें

बोर्ड की तैयारी के दौरान आपके पास सीमित समय होता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप उन विषय की तैयारी पहले शुरू करें जो आपके लिए कठिन हैं। बोर्ड की तैयारी शुरू करते समय छात्र का दिमाग



अंदर ही सभी विषय के सिलेबस को समय दे पाएंगे। आपकी यह रणनीति परीक्षा में बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा।

खाने का रखें पूरा ख्याल

अक्सर ऐसा देखा जाता है कि छात्र परीक्षा की तैयारी के दौरान खाना-पीना भी सही से नहीं लेते। इसका असर भी उनकी सेहत पर ही पड़ता है। ऐसा करने से परीक्षा की तैयारी करते समय आपके बीमार होने की संभावना बढ़

जाती है। लिहाजा आपको चाहिए कि तैयारी करते समय आप पढ़ाई के साथ-साथ आपको अपने खान-पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए।

तरोताजा होता है। ऐसे में आपको कठिन विषय की तैयारी में काफी मदद मिलेगी।

जरूरत से ज्यादा तनाव न लें

बोर्ड परीक्षा की तारीखों के नजदीक आते ही अक्सर छात्र तनाव में आ जाते हैं और वह पहले पढ़े हुए चीजों को लेकर भी संदेह में आने लगते है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप जरूरत से ज्यादा तनाव न लें। इसका विपरीत असर आपकी ही तैयारी पर भी पड़ता है। इस प्रकार आपका परीक्षा परिणाम बेहतर रहेगा।



आम तौर पर माना जाता है कि एक लाइब्रेरियन का काम सिर्फ किताबों की सही तरह से व्यवस्था करना है पर यह सही नहीं है। बल्कि लाइब्रेरियन का काम लाइब्रेरी की देखभाल व उसके लिए बजट तैयार करना होता है। इसके अलावा वह किताबों से संबंधित जानकारी व सूचनाओं को भी मुहैया

लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर शुरु करें अपना कैरियर

आज के समय में लोग भले ही सूचनाओं को कंप्यूटर या फोन पर हासिल करने लग गए हों, लेकिन फिर भी किताबों का महत्व उसी तरह बरकरार है। आज भी पढ़ने के शौकीन लोग कई तरह की किताबें, मैगजीन व अखबार आदि पढ़ना पसंद करते हैं और इसके लिए वह लाइब्रेरी का रूख करते हैं। वहां पर पत्र-पत्रिकाओं का एक बड़ा कलेक्शन मौजूद होता है और हर कोई अपनी पसंद की किताब वहां आसानी से पढ़ सकता है। अगर आपको हरदम किताबों से घिरे रहना पसंद है तो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करके बतौर लाइब्रेरियन अपना कॅरियर शुरू कर सकते हैं।

क्या होता है काम

एक लाइब्रेरियन का काम सिर्फ किताबों की सही तरह से व्यवस्था करना ही नहीं होता, बल्कि वह पूरी लाइब्रेरी की देखभाल व उसके लिए बजट तैयार करना होता है। इसके अलावा वह किताबों से संबंधित जानकारी व सूचनाओं को भी मुहैया कराता है। आसान शब्दों में, एक लाइब्रेरी को बेहतर बनाने के लिए जिन भी प्रयासों की आवश्यकता होती है, वह सभी उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।



स्किल्स

इस क्षेत्र में कदम रखने वाले छात्रों को सबसे पहले तो किताबों से लगाव होना बेहद जरूरी है। अगर आपका किताबों के प्रति रूझान नहीं है तो यह क्षेत्र आपके लिए नहीं है। इसके अलावा आपके भीतर मैनेजमेंट स्किल्स भी होने चाहिए। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतने ही बेहतर होने चाहिए।

योग्यता

इस क्षेत्र में सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर डिप्लोमा, ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स उपलब्ध हैं। अगर आप लाइब्रेरी साइंस में एक वर्षीय बैचलर डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं

कैरियर को बनाने में कुछ सहायक बातें ....

यह ऐसा समय है जबकि एक छोटी सी भूल या गलती आपको कैरियर में काफी पीछे ले जाती है। इसी वजह से कैरियर में हमें अनेक बार ऐसा अहसास होता है कि हम समय से काफी पीछे चले गए हैं। सब कुछ अच्छा होते हुए भी कुछ रह जाने का दर्द हमें सालता रहता है। ऐसे ही अहसास से छुटकारा पाने के लिए जरुरी है कुछ टिप्स अपनाने की वो इस प्रकार हैं।

दक्षता पर ध्यान दें: किसी भी क्षेत्र में दक्षता होनी आवश्यक होती है। हो सकता है कि आप समझाते हों कि आप अपने विभाग में या काम करने की जगह पर सबसे ज्यादा योग्य हैं। आपका अकेडमिक नॉलेज बेहद अच्छा है, लेकिन जब तक काम में दक्षता नहीं होगी यह सब बेकार हो जाता है। इसके लिए जरुरी है कि किताबी ज्ञान से इतर करके देखने पर अमल किया जाए। अपनी कार्य और प्रोफाइल के मुताबिक अपने आपको और अधि?क दक्ष बनाएं ताकि आपकी रुकावटें दूर हो सकें और कैरियर बेहतर हो सके।

खुद को बदलने में है समझदारी: अनेक बार हम एक ही जगह लंबे समय तक एक ही तरह का काम करते हुए स्वयं





को संतुष्ट कर लेते हैं। यह आपके कैरियर के लिए हानिकारक बात हो सकती है। एक ही जगह या एक ही कंपनी में रहना ठीक है, लेकिन कुछ नया न सीखना या न करना खुद को जांचने और परखने की बजाय जंग लगाने के बराबर है। इसलिए खुद को अप टू डेट रखने के लिए कुछ जरुरी बदलाव लाएं। नई-नई तकनीक और नए नए हुनर सीखने में कोई हर्ज नहीं है।

आत्मविश्वास लाएं अब आप भले ही योग्य और सीखे हुए हैं लेकिन इसके साथ जरुरी है कि आप में आत्मविश्वास भी हो। काफी अच्छी शिक्षा और आपका कई मायनों में दूसरों से बेहतर होना तब फायदेमंद नहीं होता जबकि आपमें आत्मविश्वास नहीं होता। ऐसे में यह सब बेकार साबित हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने अंदर आत्मविश्वास जगाएं। जरा सोचें कि जब आप आत्मविश्वास से भरे होंगे तभी तो दूसरे आपकी बात पर विश्वास करेंगे।

ईमानदारी जरुर रखें : तमाम बातों के साथ ही साथ आप अपने करियर के प्रति ईमानदार रहें, वर्ना एक छोटा सा झूठ आपके कैरियर में ग्रहण लगा सकता है। कभी भी खुद को लेकर बड़ी-बड़ी बातें न करें। ऐसा करने से लोगों को या आपके बॉस को आपसे उम्मीदें बढ़ती चली जाएंगी और तब जबकि आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे तो यह आपके कैरियर में बैरियर लगाने वाला साबित हो जाएगा। इसलिए अपने काम को बोलने दें और खुद भी ईमानदार रहें।

अतिमहत्वाकांक्षा से बचें: महत्वकांक्षी तो प्रत्येक मनुष्य को होना ही चाहिए, लेकिन अपनी महत्वकांक्षाओं के लिए अगर आप दूसरों को किनारे करेंगे तो यह आपके लिए कुछ समय तक तो सुकून या संतोष देने वाला साबित हो सकता है, लेकिन करियर को ऊंची उड़ान भरने में सहायक साबित नहीं हो सकता। ई होकर गलत कदम उठाना सही नहीं है।

न्यूज इन शॉर्ट

पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बस्तर में हुई कार्रवाई

रायपुर। राज्य शासन के निर्देशानुसार बस्तर जिला प्रशासन द्वारा प्रान्तीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारियों के खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। 13 अक्टूबर से हड़ताल पर गए जिले के 99 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस (सेवा में व्यवधान) घोषित कर दिया गया है, जबकि 17 पटवारियों को निलंबित किया गया है। अपर कलेक्टर श्री डीआर डाहिरे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले की सभी 10 तहसीलों में कुल 180 पटवारी पदस्थ हैं, जिनमें 30 प्रशिक्षु शामिल हैं। इनमें से 136 पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जबकि 44 पटवारी वर्तमान में अपने कर्तव्यों पर कार्यरत हैं। हड़ताल पर गए सभी 136 पटवारियों को प्रशासन द्वारा पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन काम पर वापस न लौटने पर यह सख्त कदम उठाया गया है। तहसीलवार आंकड़ों पर नजर डालें तो इस कार्रवाई का सबसे अधिक असर जगदलपुर और बस्तर तहसील में देखने को मिला है। जगदलपुर तहसील में पदस्थ 26 में से 25 पटवारी हड़ताल पर हैं, जिनमें से 23 पर ब्रेक इन सर्विस और 2 पर निलंबन की गाज गिरी है, जबकि यहाँ केवल एक पटवारी कार्यरत है। इसी तरह बस्तर तहसील में पदस्थ सभी 16 पटवारी हड़ताल पर हैं और प्रशासन ने सभी 16 पटवारियों का ब्रेक इन सर्विस करते हुए 2 को निलंबित कर दिया है। भानपुरी में पदस्थ 21 में से 14 हड़ताली पटवारियों पर ब्रेक इन सर्विस तथा 2 पर निलंबन की कार्रवाई हुई है, जबकि 7 कार्यरत हैं। बकावण्ड में पदस्थ 21 में से 14 हड़ताल पर हैं, जिनमें से 13 का ब्रेक इन सर्विस और एक का निलंबन किया गया है। अन्य तहसीलों में भी प्रशासन का रुख सख्त रहा है। लोहण्डीगुड़ा में पदस्थ 22 में से 11 पटवारी हड़ताल पर हैं और सभी 11 पर ब्रेक इन सर्विस के साथ 2 को निलंबित किया गया है। करपावण्ड में पदस्थ 12 में से हड़ताल पर गए सभी 10 पटवारियों का ब्रेक इन सर्विस और एक को निलंबित किया गया है। नानगुर के 10 में से 8 हड़ताली पटवारियों में से 7 पर ब्रेक इन सर्विस और 2 पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त तोकापाल में 18 में से 16 हड़ताली पटवारियों में से 2 पर ब्रेक इन सर्विस व 2 पर निलंबन, बास्तानार में 16 में से 9 हड़ताली पटवारियों में से 2 पर ब्रेक इन सर्विस व 2 पर निलंबन तथा दरभा तहसील में पदस्थ 18 में से 13 हड़ताली पटवारियों में से एक पर ब्रेक इन सर्विस व एक पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।

जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक का आयोजन 23 एवं 24 नवम्बर को कांकेर में

उत्तर बस्तर कांकेर। इस वर्ष जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक का आयोजन 23 एवं 24 नवम्बर को जिला मुख्यालय कांकेर में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता शासकीय नरहरदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंडोर स्टेडियम भवन, शासकीय भानुप्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं मिनी स्टेडियम तथा शासकीय कन्या क्रीडा परिसर कांकेर के खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार द्वारा प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों को दायित्व सौंपे गए हैं।

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का किया गया प्रारंभिक प्रकाशन

उत्तर बस्तर कांकेर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इसके तहत जिले के सभी 767 मतदान केन्द्रों में 12 नवंबर 2026 (गुरुवार) को निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है।
प्रकाशन की तिथि 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक सभी मतदान केन्द्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्त अभिहित अधिकारियों के माध्यम से मतदाताओं से दावा-आपत्ति प्राप्त की जाएगी। इस अवधि में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी युवा एवं ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे संबंधित मतदान केन्द्र के अभिहित अधिकारी अथवा बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह समीक्षा कार्यशाला का शुभारंभ

3 दिवसीय कार्यशाला में प्रदेश के 33 जिलों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे



एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

आयुक्त वीबी - जीरामजी एवं संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण श्री तारन प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में विकसित भारत-जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रक्रियाओं की बेहतर समझ एवं मैदानी स्तर पर कार्यों को गति देने के उद्देश्य से कार्यपालन अभियंता (आरईएस), सहायक परियोजना अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारियों सहित योजना के अन्य अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह समीक्षा कार्यशाला का शुभारंभ 12 नवंबर को ठाकुर प्यारेलाल सिंह राज्य ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में किया गया।

कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर आयुक्त वीबी - जीरामजी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने अपने उद्बोधन में कहा कि विकसित भारत ङ्क2047 के विजन को साकार करने के लिए योजनांतर्गत गुणवत्तापूर्ण एवं स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कार्यों के चयन में जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा जलवायु अनुकूल कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

श्री सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत आजीविका डबरी, कंटूर ट्रेंच, बालिका शौचालय एवं मुक्तिधाम शेड जैसे नवाचारपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इन कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ स्थायी ग्रामीण परिसंपत्तियों का विकास हो रहा है। प्रथम दिवस भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विकसित ग्राम पंचायत योजना के विशेषज्ञ भी शामिल होकर योजना निर्माण संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया। तीन दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण सह समीक्षा में वी बी जी राम जी योजना के विभिन्न आयामों, विकसित भारत ग्राम पंचायत प्लान सहित अन्य विषयों को सम्मिलित किया गया है।

इस अवसर पर प्रतिभागियों को तकनीकी मार्गदर्शिका पुस्तिका, 375 प्रकार के अनुमेय कार्यों की सूची, विकसित ग्राम पंचायत योजना (व्हीजीपीपी), धार-अपार एवं सुघ्घर बारी पुस्तिकाओं का वितरण भी किया गया। साथ ही विभिन्न जिलों के प्रतिभागियों को अपने अनुभवों एवं उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों को साझा करने का अवसर प्रदान किया गया।कार्यशाला 12 से 14 नवंबर 2026 तक ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर में आयोजित होगा। इस कार्यशाला में प्रदेश के सभी 33 जिलों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 12 नवंबर को 12 जिलों के प्रतिभागी, 13 नवंबर को 11 जिलों के प्रतिभागी तथा 14 नवंबर को 10 जिलों के प्रतिभागी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। कार्यशाला में विकसित भारत-जी राम जी योजना के विभिन्न प्रावधानों, क्रियान्वयन की प्रक्रिया, तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं तथा मैदानी स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में निर्वाचन संबंधी विभिन्न अधिनियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर उच्चस्तरीय बैठक संपन्न



एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध), अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ में निर्वाचन अपराधों से संबंधित विभिन्न कानूनों और उनके प्रावधानों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान निम्नलिखित प्रमुख अधिनियमों और उनके अंतर्गत आने वाले प्रावधानों की समीक्षा की गई, जिनमें छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (ङ्कह्स्), छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम शामिल हैं।

कर्मचारियों की सुविधा और प्रशासनिक संरचना पर निर्देश

बैठक के अंत में मुख्य सचिव श्री विकासशील ने प्रशासनिक कार्यों को और अधिक सुचारू बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पदों के सृजन, प्रशासनिक संरचना और पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की जाए। इसके साथ ही, मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा को देखते हुए उन्हें बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष कुमार ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, वित्त विभाग एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव अविनाश चंपावत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ मिलेंगे 13,839 रुपए बैंक खाते में होगा भुगतान

एक सत बुलेटिन ➤ उत्तर बस्तर कांकेर

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि लागत कम करना तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाना है।

धान का पूरा निर्धारित मात्रा में विक्रय करना अनिवार्य नहीं, डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापित रकबे के आधार पर मिलेगी आदान सहायता राशि

योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा, जिन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है, एग्रीस्टैक में पंजीकृत हैं तथा उनके द्वारा बोए गए धान के रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा चुका है। धान बीज उत्पादन में भाग लेने वाले किसान भी योजना के लिए पात्र होंगे। हालांकि, पंजीकृत ट्रस्ट, मंडल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एवं शाला विकास समिति जैसी संस्थाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अनुदान राशि का भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा। योजना के तहत किसानों को उनके द्वारा बोए गए धान के डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापित रकबे के आधार पर सहायता राशि दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी किसान ने 2.5 एकड़ में धान की खेती की है और पूरे रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे हो चुका है, तो उसे प्रति एकड़ 13,839 रुपये की दर से कुल 34,597.50 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। किसान द्वारा धान की निर्धारित मात्रा का पूरा विक्रय करना अनिवार्य नहीं है। कम मात्रा में धान विक्रय करने पर भी सत्यापित रकबे के अनुसार सहायता राशि की पात्रता रहेगी।

कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य है।

राजस्व कार्यों में लापरवाही पर खैरागढ़ जिले के तीन पटवारी निलंबित

गंभीर प्रकरणों में सेवा से पृथक करने तक की चेतावनी

एक सत बुलेटिन ➤ उत्तर बस्तर कांकेर

रायपुर। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों में लापरवाही, समय-सीमा में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने के मामलों में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वहीं, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गंडई-छुईखदान द्वारा हड़ताली पटवारियों को जारी अंतिम कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय कार्य नहीं करने एवं निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। गंभीर प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके अतिरिक्त जिले में हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण नहीं किया गया है। गंडई, छुईखदान एवं साल्हेवारा तहसीलों के हड़ताली पटवारियों को 30 अक्टूबर को जारी अंतिम कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया है कि संबंधित पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहकर शासकीय कर्तव्यों से विरत हैं। इससे डिजिटल क्रॉप सर्वे का अनुमोदन, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन जैसे शासन के महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। नोटिस में आगामी धान खरीदी के दृष्टिगत फसल संबंधी अभिलेखों का समय पर अनुमोदन आवश्यक बताते हुए कहा गया है कि कार्य लंबित रहने से किसानों एवं आम नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नोटिस में पूर्व में 16 अक्टूबर को दिए गए निर्देशों का उल्लेख करते हुए संबंधित पटवारियों को अंतिम अवसर प्रदान किया गया था।

सेवा में व्यवधान संबंधी कार्रवाई

उन्हें 2 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे तक निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करने, संबंधित तहसीलदार को सूचना देने और डिजिटल क्रॉप सर्वे सहित लंबित कार्यों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय में उपस्थित नहीं होने पर अनुपस्थिति को नियमानुसार अनधिकृत मानकर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करने की चेतावनी दी गई थी। नोटिस में लागू प्रावधानों के अनुसार 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर निर्णय तथा सेवा में व्यवधान संबंधी कार्रवाई की संभावना भी स्पष्ट की गई है। निलंबन की कार्रवाई के अंतर्गत तहसील खैरागढ़ के पटवारी हल्का क्रमांक 35 एवं 36 में पदस्थ आकाश सिंह राजपूत को स्वामित्व योजना एवं किसान पंजीयन सत्यापन के कार्यों में प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही के आधार पर निलंबित किया गया है। आदेश के अनुसार स्वामित्व योजना के आवश्यक प्रतिवेदन विलंब से प्रस्तुत किए गए, जबकि दो ग्रामों के प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे पात्र ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों के वितरण में विलंब हुआ। साथ ही एग्रीस्टैक पोर्टल पर कॉमन सर्विस सेंटर से प्राप्त धान पंजीयन संबंधी आवेदन उनकी आईडी में सत्यापन के लिए लंबित पाए गए। तहसील छुईखदान के माध्यम से किसान पंजीयन संबंधी कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर निलंबित किया गया है।

पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हुई कार्रवाई

एक सत बुलेटिन ➤ जगदलपुर

राज्य शासन के निर्देशानुसार बस्तर जिला प्रशासन द्वारा प्रान्तीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे पटवारियों के खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। 13 अक्टूबर से हड़ताल पर गए जिले के 99 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस (सेवा में व्यवधान) घोषित कर दिया गया है, जबकि 17 पटवारियों को निलंबित किया गया है।

अपर कलेक्टर श्री डीआर डाहिरे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले की सभी 10 तहसीलों में कुल 180 पटवारी पदस्थ हैं, जिनमें 30 प्रशिक्षु शामिल हैं। इनमें से 136 पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जबकि 44 पटवारी वर्तमान में अपने कर्तव्यों पर कार्यरत हैं। हड़ताल पर गए सभी 136 पटवारियों को प्रशासन द्वारा पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन काम पर वापस न लौटने पर यह सख्त कदम उठाया गया है। तहसीलवार आंकड़ों पर नजर डालें तो इस कार्रवाई का सबसे अधिक असर जगदलपुर और बस्तर तहसील में देखने को मिला है। जगदलपुर तहसील में पदस्थ 26 में से 25 पटवारी हड़ताल पर हैं, जिनमें से 23 पर ब्रेक इन सर्विस और 2 पर निलंबन की गाज गिरी है, जबकि यहाँ केवल एक पटवारी कार्यरत है। इसी तरह बस्तर तहसील में पदस्थ सभी 16 पटवारी हड़ताल पर हैं और प्रशासन ने सभी 16 पटवारियों का ब्रेक इन सर्विस करते हुए 2 को निलंबित कर दिया है। भानपुरी में पदस्थ 21 में से 14 हड़ताली पटवारियों पर ब्रेक इन सर्विस तथा 2 पर निलंबन की कार्रवाई हुई है, जबकि 7 कार्यरत हैं। बकावण्ड में पदस्थ 21 में से 14 हड़ताल पर हैं, जिनमें से 13 का ब्रेक इन सर्विस और एक का निलंबन किया गया है।

अन्य तहसीलों में भी प्रशासन का रुख सख्त रहा है। लोहण्डीगुड़ा में पदस्थ 22 में से 11 पटवारी हड़ताल पर हैं और सभी 11 पर ब्रेक इन सर्विस के साथ 2 को निलंबित किया गया है।

बस्तर के हुनर की राष्ट्रीय पहचान

राष्ट्रपति भवन से कोंडागांव के 11 शिल्पकारों को बुलावा, लोहे की 700 घंटियों ने बढ़ाया गौरव

एक सत बुलेटिन ➤ कोंडागांव

बस्तर की माटी में रचा-बसा पारंपरिक हुनर अब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन तक अपनी चमक बिखेर रहा है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की उत्कृष्ट बेलमेटल और लौह शिल्पकला को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष सम्मान मिला है। राष्ट्रपति भवन की ओर से भेजे जाने वाले विशेष आमंत्रण पत्रों की सजावट के लिए कोंडागांव के शिल्पकारों द्वारा तैयार कलाकृतियों का चयन किया गया है। कलाकारों की बेजोड़ कारीगरी से प्रभावित होकर राष्ट्रपति भवन ने जिले के 11 हस्तशिल्पियों को विशेष आमंत्रण भेजा है। यह उपलब्धि न केवल कोंडागांव के कलाकारों के लिए गौरव का अवसर है, बल्कि बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पीढ़ियों से सहेजी जा रही पारंपरिक कला के सम्मान का भी प्रतीक है। राष्ट्रपति भवन से मिले इस आमंत्रण के बाद कलाकारों का दल दिल्ली जाने की तैयारियों में जुट गया है।

स्थानीय हुनर ने बनाई राष्ट्रपति भवन तक पहचान

कोंडागांव की पारंपरिक शिल्पकला अब स्थानीय बाजारों की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान स्थापित कर रही है। जिले के कलाकारों द्वारा तैयार बेलमेटल और लौह शिल्प की कलाकृतियों को राष्ट्रपति भवन के विशेष निमंत्रण पत्रों की सजावट में स्थान मिला है। महाराष्ट्र, गोवा और छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों की चयनित हस्तशिल्प सामग्रियों में कोंडागांव की कलात्मक वस्तुओं को भी शामिल किया गया है।छत्तीसगढ़ पर्यटन गाइडविशेष आमंत्रण पत्रों की सजावट में बस्तर की शिल्पकला का चयन स्थानीय कलाकारों की रचनात्मकता और उत्कृष्ट कारीगरी को मिलने वाली बड़ी पहचान है। इस उपलब्धि ने कोंडागांव के पारंपरिक शिल्प को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने का अवसर प्रदान किया है।



लोहे की 700 घंटियों में दिखाई दिया बस्तर का अद्भुत हुनर

कोंडागांव जिले के ग्राम किड़ईछेपड़ा के शिल्पकारों ने अपनी मेहनत और कलात्मक कौशल से इस उपलब्धि को खास बनाया है। गांव के सुनील विश्वकर्मा, अनिल विश्वकर्मा और नगीना विश्वकर्मा ने मिलकर लोहे की 700 आकर्षक घंटियों का निर्माण किया था। इन घंटियों में कलाकारों की पारंपरिक कारीगरी और रचनात्मकता की सुंदर झलक दिखाई देती है। इन्हीं कलाकृतियों ने कोंडागांव के लौह शिल्प को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साधारण लोहे को आकर्षक कलात्मक स्वरूप देने वाले इन शिल्पकारों का हुनर अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है। यह सफलता पीढ़ियों से पारंपरिक कला को संजोकर रखने वाले कलाकारों के लिए विशेष सम्मान है।

शुक्रवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगे 11 शिल्पकार

राष्ट्रपति भवन से विशेष आमंत्रण मिलने के बाद कोंडागांव जिले के 11 हस्तशिल्पियों का दल शुक्रवार को दिल्ली के लिए रवाना होगा। इस दल में पारंपरिक बेलमेटल कलाकारों के साथ आठ लौह शिल्पकार भी शामिल हैं। दिल्ली जाने की तैयारियों में जुटे कलाकार अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ भेंट स्वरूप ले जाने वाली कलात्मक वस्तुओं को भी तैयार कर रहे हैं। कलाकार अपने साथ बस्तर की विशिष्ट शिल्प परंपरा की झलक प्रस्तुत करने वाली कलाकृतियां लेकर जाएंगे। जिला प्रशासन की ओर से कलाकारों की दिल्ली यात्रा और प्रवास के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। राष्ट्रपति भवन से प्राप्त विशेष आमंत्रण के बाद कलाकारों के दिल्ली जाने की तैयारियां की जा रही हैं।